बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 283

विमानन हब

खबरों के मुताबिक पूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली देश की इकलौती विमानन सेवा एयर इंडिया स्वयं को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास में है। इनमें भारत आने और यहां से बाहर जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ वे यात्री भी शामिल हैं जिन्हें दो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों की यात्रा के दरमियान भारतीय हवाई अड्डों को ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल करना अनुकूल लग सकता है। विमानन कंपनी ने कहा है कि दिल्ली हवाई अड्डा जो देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, वहां देश के हवाई क्षेत्र से हर साल गुजरने वाले 13 करोड़ यात्रियों के सौवें हिस्से से भी कम यात्री आते हैं। इसकी तुलना में दुबई में 10 फीसदी और दोहा में साढ़े सात फीसदी यात्री रुकते हैं। स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है। विमानन कंपनी यह भी मानती है कि अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के लिए और सीधी उड़ानें कंपनी के लाभ को बढ़ा सकती हैं। यकीनन कंपनी के पास कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में आकर्षक लैंडिंग स्लॉट हैं जिनका वह बेहतर इस्तेमाल कर सकती है।

घरेलू बाजार में एयर इंडिया की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी किफायती विमानन सेवा इंडिगो है। उसने भी पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय परिचालन बढ़ाया है। उदाहरण के लिए खबरों के मुताबिक नियामकों द्वारा भारतीय विमानन कंपनियों को वेट लीजिंग (चालक दल और यात्रियों सहित विमान किराये पर लेना) के प्रतिबंधों को शिथिल किए जाने के बाद इंडिगो यूरोप में कनेक्टिंग उड़ानों के लिए स्कैंडिनेवियन एयरलाइन के साथ ऐसी व्यवस्था बनाने की संभावना तलाश रही है। कंपनी ने फिलहाल टर्किश एयरलाइन के साथ एक समझौता किया हुआ है जिसके तहत वह यात्रियों को भारत से इस्तांबुल पहुंचाती है जहां से वे यूरोप के अलग-अलग शहरों में जाते हैं। वह लंदन एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उसे मैनचेस्टर से ही संतुष्ट होना पड़े। अगर ऐसा होता है तो वह बड़े घरेलू नेटवर्क का लाभ लेकर यात्रियों को दिल्ली में अपने हब से ब्रिटिश एयरपोर्ट ले जा सकेगी।

क्षेत्रवार वृद्धि और यात्रियों के लिए अनुकूलता बढ़ाने का यह अवसर हवाई अड्डा परिचालकों और नियामकों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग की मांग करता है। एक अंतरराष्ट्रीय हब तैयार करना आसान नहीं है। दिल्ली के कुल टैरिफ का केवल 20 फीसदी ही एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों का है। इसमें सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है। बहरहाल इस कम आंकड़े की वजहें और भारत के निकट दुबई और सिंगापुर जैसे ट्रांजिट हबों की लोकप्रियता को भी सही तरह से समझना होगा। वे हवाई अड्डे किफायती हैं, कम स्थानांतरण समय का वादा करते हैं और बहुत अधिक विश्वसनीय हैं। उनके संपर्क भी भारत के किसी भी अन्य हवाई अड्डे से बेहतर हैं। ऐसे हवाई अड्डों की कामयाबी के लिए उन एयरलाइनों को द्विपक्षीय लैंडिंग अधिकार देने के पुराने फैसलों को दोष देना बहुत आसान है जो उन्हें हब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न यह किया जाना चाहिए कि यात्रियों ने विकल्प दिए जाने के बाद भी उन्हें ही क्यों पसंद किया।

प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने के काम में प्रासंगिक अधिकारियों के सहयोग के बिना इन प्रयासों को कामयाबी मिलती नहीं दिखती। ऐसी ही एक जरूरत है प्रक्रियाओं को सुसंगत बनाने की जिसमें सीमा शुल्क शामिल है। यात्रियों के सामान की जांच आसान होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट के लिए शेड्यूल में बदलाव करना होगा ताकि अनुकूल स्थानांतरण समय तय किया जा सके और सामान के निपटान के प्रोटोकॉल को दिल्ली जैसे हवाई अड्डों पर बेहतर बनाना होगा। हवाई अड्डे की क्षमता में विस्तार का वादा भी बहुत समय से लंबित है। गत वर्ष दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा था कि वह व्यस्ततम समय की क्षमता में करीब एक तिहाई का इजाफा करेगा ताकि हर घंटे 110 उड़ानों और लैंडिंग की देखरेख हो सके। बड़ी विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों की महत्त्वाकांक्षाएं समान हैं। नियमन, निगरानी और क्षमता को अपनाकर इन आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है।

अजय मोहंती

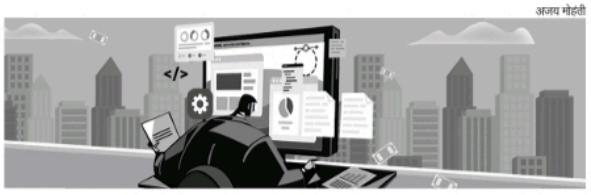

दुनिया में आ रहा है फ्रीलांस का दौर

अमेरिका ही नहीं भारत में भी फ्रीलांस करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था में इससे काफी योगदान हो रहा है। बता रहे हैं अजित बालकृष्णन

भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) कलकत्ता से स्नातक करने के बाद सन 1971 में जब मैंने बंबई में पहली नौकरी शुरू की तो मैं चकित रह गया था: मेरे सामने जो दफ्तर था वहां 50 फीसदी हिस्सा युवक-युवतियों से भरा था। उनके सामने टाइपराइटर रखे थे और टाइपिंग करने के लिए वे उनके कीबोर्ड को पीटे जा रहे थे। मैं जिस दफ्तर में था, वह उस समय देश की सबसे रचनात्मक विज्ञापन एजेंसी का दफ्तर था। मैं 21 वर्ष का था और मेरा दिमाग घूमने लगा: क्या इस कंपनी ने अखबारों में छपने वाले वे सभी शानदार विज्ञापन इसी तरह बनाए हैं? क्या मशीनी टाइपराइटर का इस्तेमाल ही सबको रचनात्मक बना रहा था?

आज भी जब मैं ऐसी कंपनियों के बारे में सुनता हूं, जहां हजारों कर्मचारी दफ्तर में बैठकर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो अचरज में पड़ जाता हूं। फिर कंपनी चाहे वित्तीय क्षेत्र की हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हो या किसी अन्य क्षेत्र की। साथ ही मैं सोचने लगता हूं कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के विकास के साथ दफ्तरों से क्या ये पर्सनल कंप्यूटर भी उसी तरह गायब हो जाएंगे, जैसे कंप्यूटर आने के बाद टाइपराइटर और टाइपिस्ट दफ्तरों से खत्म होने लगे थे। क्या पर्सनल कंप्यूटरों पर काम करने वाले ये युवक-युवतियां भी इसी तरह दफ्तरों से विदा हो जाएंगे?

भविष्य में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं इसके कुछ संकेत हालिया खबरों में नजर आते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े देखिए, '2024 में तकरीबन 38 फीसदी अमेरिकी कामगार यानी लगभग 6.4 करोड़ लोग फ्रीलांस कामकाज कर रहे हैं। इस अनुमान के अनुसार 2027 तक अमेरिका की कुल श्रम शक्ति में करीब 50 फीसदी लोग फ्रीलांस काम करने वाले हो सकते हैं।'

गहराई से पड़ताल करने पर पता चलता है कि यह रुझान इसलिए नहीं आया है कि नियोक्ता अपने दफ्तरों में पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं बल्कि कर्मचारी खुद ऐसा चाह रहे हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ जब मध्य वर्ग के हम सभी लोग मानते थे कि किसी दफ्तर में पूर्णकालिक या स्थायी कर्मचारी होना एक तरह से खुशहाल जीवन की गारंटी है।

आगे और जानकारी जुटाने पर पता चलता है कि जेन जी (1997 से 2010 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी) के तकरीबन 52 फीसदी सदस्य और मिलेनियल (1981 से 1996 के बीच जन्मे) आबादी के 44 फीसदी लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लोग युवा हैं, वे फ्रीलांस कामकाज कर रहे हैं। मुझे लगता था कि इन फ्रीलांसरों में अधिकतर वे लोग होंगे, जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली होगी और जो कम वेतन वाले एक काम से दूसरे काम के बीच भागाभागी करते होंगे। परंतु खबरों के मुताबिक आधे से अधिक फ्रीलांसरों के पास स्नातकोत्तर डिग्री है। इससे संकेत मिलता है कि स्वतंत्र रूप से काम करने वालों में भी उच्च शिक्षित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। यह भी संभव है कि युवा महिलाएं रोजाना दफ्तर में घंटों बिताने के बजाय फ्रीलांसिंग करना पसंद कर रही हों क्योंकि इससे उन्हें अपने छोटे बच्चों की देखभाल करने का भरपूर समय मिल जाता है। परंतु सवाल का सही जवाब इससे भी नहीं मिलता क्योंकि फ्रीलांसिंग करने वालों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या करीब बराबर ही है। इनमें 52.3 फीसदी महिलाएं और 47.7 फीसदी पुरुष हैं। जाहिर है कि फ्रीलांसिंग चुनने के पीछे कोई और वजह काम कर रही है।

इसके अलावा शोध बताता है कि ये नई पीढ़ी काम करने का समय खुद तय करना पसंद करती हैं और वे परियोजनाएं ही चुनती हैं, जो उन्हें दिलचस्प लगती हैं। साथ ही ये काम और निजी जीवन में संतुलन कायम करने का प्रयास करती हैं। फ्रीलांसिंग में उन्हें जगह चुनने, अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखने, सार्थक काम करने और लीक से हटकर करियर चुनने का मौका मिलता है। फ्रीलांसर सीमाओं के पार यानी विदेश के क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। इससे उन्हें उच्च आय अर्जित करने तथा तरह-तरह के लोगों के साथ काम करने के अवसर मिलते हैं। वैश्विक प्लेटफॉर्म कुशल कर्मचारियों को ऊंचे मेहनताने वाले बाजारों की मांग पूरा करने लायक बनाते हैं।

अमेरिका की अर्थव्यवस्था में फ्रीलांसरों को अहम योगदान है। फोर्ब्स के मुताबिक 2023 में उनकी कुल आय करीब 1.27 लाख करोड़ डॉलर रही। शायद अब समय आ गया है कि नीति निर्माता फ्रीलांसरों को अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा मानें और ऐसे कानून बनाएं, जिससे यह बात साबित भी होती हो। अगर आपको लगता है कि यह सब केवल अमेरिका में हो रहा है और भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा तो नीति आयोग के कुछ आंकड़े लिए पेश हैं। 2020-21 में हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 77 लाख गिग (फ्रीलांस के लिए दूसरा शब्द) कर्मचारी थे, जिनकी संख्या 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ पर पहुंच जाएगी।

देश के फ्रीलांस कर्मियों का बड़ा हिस्सा आईटी क्षेत्र में काम करता है और वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तथा साइबर सिक्युरिटी के क्षेत्र में काम कर रहा है। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया प्रबंधन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कामों में भी फ्रीलांसर काफी ज्यादा हैं।

ऑनलाइन कोचिंग, पाठ्यक्रम तैयार करमने और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट तैयार करने के क्षेत्र में भी फ्रीलांस काम बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योग प्रशिक्षक, फिटनेस प्रशिक्षक, आहार विशेषज्ञ और मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार भी वर्चुअल तथा निजी तौर पर फ्रीलांस सेवाएं दे रहे हैं। फ्रीलांस पत्रकार, ब्लॉगर और संपादक भी मीडिया संस्थानों तथा स्वतंत्र मंचों के लिए काम करते हैं। इससे उन्हें स्थानीय मुद्दों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मामलों तक अलग-अलग विषयों पर काम करने का मौका मिल जाता है।

थोड़ा सोचने पर मुझे अहसास हुआ कि भारत में भी कुछ लोग लंबे समय से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अंतर इतना है कि उन्हें फ्रीलांसर के बजाय 'प्राइवेट प्रैक्टिशनर' कहा जाता है। उदाहरण के लिए दशकों से डॉक्टरों, अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों का एक बड़ा धड़ा निजी तौर पर काम यानी प्राइवेट प्रैक्टिस करता आया है। मेरे पिता और नाना डॉक्टर थे तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। इसे मध्य वर्ग में स्वीकार्य और सम्मानजनक माना जाता था। माना जा सकता है कि आज भारत में 80 फीसदी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं और देश में 13 लाख पंजीकृत वकीलों का बड़ा हिस्सा तथा 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंटों में से 40 फीसदी ऐसे ही काम करते हैं।

अब अंतर यह आ गया है कि डिजिटल तकनीक फ्रीलांस अर्थव्यवस्था में खास भूमिका निभा रही है। उदाहरण के लिए ईमेल, चैट ऐप और वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि के जरिये तात्कालिक संवाद संभव है, जिससे सेवा प्रदान करना आसान हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों और ऑनलाइन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की मदद से पहुंच बढ़ी है। अब यह पेशा किसी एक शहर, कस्बे या भौगोलिक इलाके तक सीमित नहीं है बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये फ्रीलांसर अधिक आकर्षक बाजारों तक पहुंच रहे हैं।

तो आइए, फ्रीलांस अर्थव्यवस्था का स्वागत करें क्योंकि यह दुनिया के हर पेशे में पैठ बना रही है।

नए एवं रचनात्मक प्रबंधन कौशल का अभाव

दिग्गज कंपनियों जैसे गूगल (अल्फाबेट) और माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई और सत्य नडेला अक्सर यहां आते रहते हैं। उनकी भारत यात्रा से साथ कई बातें जुड़ी रहती हैं मगर उनमें एक खास बात यह है कि वे देश के मध्यम वर्ग के लोगों को गौरवान्वित महसूस करने का मौका देते हैं। अल्फाबेट के पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के नडेला दोनों ही भारत में संसाधन के रूप में मानव पूंजी की बेहद कमी का विनम्रता से जिक्र करते हैं। नडेला ने हाल में अपने भारत दौरे पर कहा, 'इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भारत की मानव पूंजी का लाभ नहीं उठा रहे वे होड़ ही नहीं करना चाहते।'

नडेला के इस कथन को कुछ ही दिनों में अमेरिका की सत्ता संभालने जा रहे डॉनल्ड ट्रंप के लिए बेहद जरूरी संदेश माना जा सकता है। नडेला कहना चाह रहे होंगे कि नई सरकार को एच-1बी वीजा नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिलिकन वैली पिछले कई दशकों से भारतीय प्रतिभाओं को दम पर फलता-फूलता रहा है। नडेला के बयान की व्याख्या भारत में तेजी से उभरते वैश्विक क्षमता केंद्रों की बढ़ती अहमियत के रूप में भी की जा सकती है। इन केंद्रों के जरिये अमेरिकी कंपनियां सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के होनहार एवं शिक्षित भारतीयों का भरपूर फायदा उठाती हैं और वह भी बेहद कम वेतन पर।

ऐसे सराहना करने वाले बयानों की व्याख्या आम तौर पर इसी तरह होती है। भारतीय मूल के कुछ सफल सीईओ दरअसल इस विषय पर ध्यान खींचना चाहते हैं कि भारतीय कंपनी जगत में नडेला, पिचाई या अन्य सफल पेशेवर एवं प्रबंधक तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आखिर भारतीय कंपनियों में देश के शीर्ष इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन संस्थानों ने निकले मेधावी लोगों की कमी तो नहीं है।

पिछले कुछ दशकों के दौरान भारतीय आर्थिक नीति की ढांचागत बंदिशों और अधिकारियों की लालफीताशाही जैसी समस्याओं पर काफी कुछ लिखा और कहा जा चुका है। ये तर्क एक सीमा तक ठीक भी लगते हैं। मगर बंदिशों में बांधने वाले उस प्रबंधन तंत्र के बारे में खुलकर नहीं बता पा रहे, जो भारतीय कंपनियों ने शायद खुद ही चुना है। जिस बात की बहुत कम चर्चा होती है वह है भारतीय कंपनियों में वाजिब मेधा-आधारित व्यवस्था नहीं होना। भारत के सबसे बड़े कारोबारी प्रतिष्ठान परिवार नियंत्रित हैं और नीतियां तैयार करने वाला उनका प्रबंध तंत्र संस्थापक परिवार के भीतर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऊर्जावान और शीर्ष स्तर के प्रबंधकों की कमी है। मगर संगठन के भीतर वरिष्ठों के मातहत काम करने की व्यवस्था (सीनियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर) में प्रबंधन की नई सोच पनप ही नहीं पाती। इस व्यवस्था या ढांचे में कंपनी के मालिक के पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी, भाई, भतीजे और दूसरे सगे-संबंधियों को ज्यादा अहमियत दी जाती है।

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

ध्यान देने वाली बात है कि जिन अमेरिकी कंपनियों की कमान इस समय भारतीय मूल के लोगों के हाथों में है, उनमें से कई कंपनियां किसी समय संस्थापकों के हाथों में ही थीं। इनमें गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, पेप्सी, आईबीएम के नाम गिनाए जा सकते हैं। मगर कोई भी उन्हें भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की तरह परिवार के हाथों चलने वाली कंपनी नहीं कहेगा। इनमें से ज्यादातर कंपनियों के संस्थापक एक समय के बाद बागडोर योग्य लोगों को हाथों में सौंपना शुरू कर देते हैं। इस तरह वे अपनी नई कंपनियों या स्टार्टअप को बाजार के तौर-तरीकों में ढाल देते हैं, प्रबंधन में पेशेवर मेधाओं को जगह देते हैं और प्रतिभा एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाला माहौल तैयार करते हैं।

इससे समझ आ सकता है कि तेजी से उभरती और नई सोच वाली भारतीय कंपनियां स्टार्टअप क्षेत्र से ही क्यों आ रही हैं, जहां युवाओं को परिवार के प्रबंधन वाले घुटन भरे माहौल से बाहर आजादी से काम करने का मौका मिलता है। यह बात कंपनियों के निदेशक मंडल (बोर्ड) पर भी उतनी ही लागू होती है। पश्चिमी देशों में बोर्ड खराब प्रदर्शन करने वाले संस्थापकों या सीईओ को निकालने में (ऐपल, एचपी, याहू और उबर इसके अच्छे उदाहरण हैं) बिल्कुल हिचक नहीं दिखाते। मगर पुराने तरीके से चलने वाली किसी भी भारतीय कंपनी में प्रवर्तक या सीईओ को बाहर करने की हिम्मत आज तक कोई बोर्ड नहीं दिखा पाया है। उन लोगों के खिलाफ भी बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया, जिनके कारनामे खुलकर सामने आ चुके हैं। फिर चाहे सत्यम हो या येस बैंक, जहां कंपनियों की कमान संस्थापक सीईओ के हाथों में थी और उन्हें हटाने के लिए खुद नियामकीय एजेंसियों को हरकत में आना पड़ा।

लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारतीय स्टार्टअप कंपनियों का प्रबंधन कौशल अनुकरणीय है। ग्लासडोर डॉट कॉम पर डाली गई टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि उनके भीतर कामकाजी माहौल किस कदर खराब और दमघोंटू है और अक्सर इसका कारण भी स्टार्टअप कंपनियों के संस्थापक ही होते हैं। मगर दो कारक शक्तिशाली-सीईओ को अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकते हैं। पहला, सह-संस्थापक आम तौर पर कुछ पेशेवर होते हैं या पुराने दोस्त होते हैं, जो नया कारोबार शुरू करने के लिए साथ आए होते हैं। उस सूरत में काम करने के लिए मेधा तो पहली शर्त होती ही है। दूसरा, स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल (वीसी) और प्राइवेट इक्विटी (पीई) से पूंजी जुटाई जाती है, इसलिए उन पर लगातार नजर रखी जाती है। अंतर साफ नजर आता भी है। हाउसिंग डाट कॉम के निदेशक मंडल ने 2015 में संस्थापक सदस्यों में से एक राहुल यादव को उनके प्रतिकूल व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया था, जबकि राहुल उस समय कंपनी के सीईओ थे। 2022 में भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर को भी कंपनी के बोर्ड ने लापरवाही और अनियमितता बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया।

अब जरा एडटेक कंपनी बैजूस पर विचार कीजिए, जिसने एकाएक बड़ी ऊंचाइयां छू ली थीं। अब यह कंपनी कर्ज के बोझ में दब चुकी है और कानूनी विवादों तथा दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही है। बैजूस हमेशा से परिवार के नियंत्रण वाली कंपनी ही रही, जिसे खुद संस्थापक, उनकी पत्नी और भाई चला रहे हैं। वे लोग निदेशकों की सलाह को भी ताक पर रख रहे थे और जब इस बात का अहसास स्वतंत्र निदेशकों को हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मगर ज्यादातर भारतीय कंपनियों के बोर्ड में ऐसा नहीं दिखता। उनमें स्वतंत्र निदेशक प्रवर्तकों पर निर्भर होते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं और उनकी योजनाओं पर बिना किसी हिचकिचाहट के मुहर लगा देते हैं।

किसी भी देश को शिक्षित और सेहतमंद श्रमबल की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत 'मानव पूंजी' संसाधन की भी है और रचनात्मक तथा नई सोच रखने वाला प्रबंधन इस संसाधन की कुंजी है। भारत में दोनों की ही कमी है और संभवतः यही कारण है कि वैश्विक कारोबारी पटल पर भारतीय कंपनियों का रुतबा बहुत कम है।

आपका पक्ष

विदेशों में स्वदेशी ब्रांड

लेख 'विदेशों में देसी ब्रांड' पर हल्दीराम और अमूल ब्रांड के उदाहरण के साथ बहुत गहन और सम्यक चर्चा की गई है। भारतीय स्वदेशी ब्रांड के वैश्विक व्यापार में प्रभावशाली होने के महत्त्व को भारत के विदेशी व्यापार में संवर्धन की दृष्टि से कॉरपोरेट नीति निर्धारकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात को समझा जाए कि किन कारणों से भारतीय ब्रांड वैश्विक व्यापार में पीछे हैं। इसके लिए सरकार से अधिक हमारे उद्योग व्यापार और बड़े कॉरपोरेट की भूमिका और उनकी विस्तार की नीति की समीक्षा आवश्यक है। उनका पूंजी और औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे हैं। इसलिए वह अपने क्षेत्र में समानांतर कंपनियों के साथ समझौते या अधिग्रहण कर अपना पूंजी और औद्योगिक उत्पादन क्षमता को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बढ़ाएं। हमारी स्वदेशी कंपनियां शोध और नवोन्मेष द्वारा विदेशी मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों का उत्पादन करे और अपनी गुणवत्ता को उन्नत करे। देश में छोटे, बड़े और मध्यम उद्योग व्यापार परिवारों के नियंत्रण में है। इससे उनके उद्योग व्यापार सीमित हैं। घरेलू बाजार में हर क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रांड है। अतः बड़े पूंजीगत आधार और औद्योगिक उत्पादन क्षमता के साथ वैश्विक बाजार में स्थापित करने की जरूरत है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

देश में स्वदेशी ब्रांडों को और अधिक उन्नत बनाने की जरूरत है जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके

परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए एआई का सहारा

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) ने परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई मॉड्यूल का उपयोग करने की योजना बनाई है जो स्वागत योग्य है। विभिन्न परीक्षाओं की पवित्रता व गोपनीयता कायम रखने के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को अपने आवेदन फॉर्म आधार से लिंक करने के निर्देश दिए जाएं। इससे उनके फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ कभी भी जांचे जा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से फॉर्म लिंक नहीं हो पाते हैं, उनकी भर्ती परीक्षा अलग परीक्षा केंद्र पर आयोजित कराई जाए। परीक्षा केंद्र व परीक्षा से संबंधित अमले का चयन काफी सावधानीपूर्वक करना होगा। जहां तक डमी अभ्यर्थियों का सवाल है, तो उसके लिए एआई का सहारा लिया जा सकता है। अगर किसी भी तरीके से डमी अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठ भी गया तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को रोक लिया जाए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

हिमालय की गूंज और भूकंप की चुनौतियां

पिछले दिनों तिब्बत में आए भूकंप ने हमें एक बार फिर प्राकृतिक अनिश्चितता का आभास कराया है। हिमालय जैसी भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखला के करीब बसे होने के कारण, भारत जैसे देश भूकंप के जोखिम से लगातार जूझते रहते हैं। भारत में कई इमारतें खासकर ग्रामीण इलाकों में, भूकंपरोधी मानकों पर खरा नहीं उतरती हैं। बेतरतीब शहरीकरण और भवन निर्माण कानूनों का उल्लंघन भी इस समस्या को और गहरा बना रहा है। भूकंपरोधी तकनीकों से इमारतों का निर्माण, आपदा प्रबंधन के माध्यम से हम इसका सामना कर सकते हैं।

राजूराम प्रजापत, नागौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को मैड्रिड में स्पेन के राजा फेलिपे VI से मुलाकात की। जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 16 जनवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

उत्साह जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके पास यह है, तो जीत आपकी है।

-संत प्रवर श्री चंद्रप्रभ जी

हल नहीं है डॉट डॉट डॉट

आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नसीहत और चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर पीओके के बिना अधूरा है। इस क्षेत्र को आतंकवाद के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए रक्षा मंत्री ने इसकी भूमि प्रशिक्षण शिविरों और घुसपैठ गतिविधियों के लॉन्च पैड के तौर पर करने की बात कही। रक्षा मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के अखनूर में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इसकी पक्की जानकारी भारत के पास है, पाकिस्तान को यह बीमारी खत्म करनी होगी, नहीं तो डॉट-डॉट-डॉट। पीओके के लोगों को सम्मानजनक जीवन से वंचित रखने और धर्म के नाम पर उनका शोषण करने की भी उन्होंने चर्चा की। पीओके के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा

कि यह जिया-उल-हक के समय से पोषित भारत विरोधी एजेंडा का हिस्सा है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक ने बीते हफ्ते जिहादी संस्कृति को फिर जीवित करने की घोषणा की है। जिहाद की वकालत कर, अल-जिहाद के नारे लगवाने के पीछे उनकी मंशा इलाके की शांति भंग कर स्थिरता को ठेस लगाने की है। भारत-पाकिस्तान के दरम्यान 1965 में अखनूर में ही युद्ध लड़ा गया था। 1948, 1965, 1971 से लेकर 99 तक पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी परंतु घुसपैठ की घटनाएं रुकी नहीं हैं। न ही लगातार अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने की नीति छोड़ रहा है। सरकार का दावा है कि धारा 370 को हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में महत्त्वपूर्ण बदलाव नजर आ रहा है। राज्य की अब्दुल्ला सरकार ने भी लचीला रुख अख्तियार किया है। सरकार इस इलाके को भारत के माथे के मुकुट का मणि बताते हुए लंबे समय से दावा कर रही है कि वह पीओके को वापस लेने के प्रति गंभीर है। पाकिस्तान का भारत विरोधी रुख किसी से छिपा नहीं है। शांति के प्रति उदासीन इस पड़ोसी मुल्क के पास आंतरिक समस्याओं का इतना अंबार है कि वह अंतरराष्ट्रीय मसलों के प्रति उपेक्षा भाव अपनाए रहने को मजबूर लगता है। सैनिकों की हौसलाफजाई तक तो ठीक है परंतु जब उस पर डपट काम नहीं करती तो यूं डॉट-डॉट-डॉट जैसे हर्फों का क्या असर हो सकता है। कोरी धमकियों की बजाय अब सरकार को स्पष्ट तौर पर उंगली टेढ़ी करने से परहेज नहीं करना चाहिए।

क्रूर अपेक्षा

कभी-कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति के मुंह से कुछ इस तरह के बयान निकल कर बाहर आ जाते हैं जिनके बारे में तय करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें गंभीर मान कर इन पर समुचित ध्यान दिया जाए या हास्यास्पद मान कर दरकिनार कर दिया जाए। पिछले दिनों लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) के चेयरमैन एस. एन. सुब्रमण्यम ने जो बात कही उस पर पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने अपने कर्मचारियों की बैठक में कहा कि कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे और रविवार को भी काम करना चाहिए। अपनी पत्नियों का मुंह निहारने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इससे पहले इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति भी कर्मचारियों से सप्ताह में 70 घंटे काम करने का आह्वान कर चुके हैं। अगर इन टिप्पणियों को सचमुच गंभीरता से लिया जाए तो ये बहुत क्रूरता, नासमझी और असंवेदनशीलता से भरी हुई टिप्पणियां हैं। इनका निहित भाव यह है कि कर्मचारी न अपने परिवार पर ध्यान दें, न दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों से संपर्क रखें और अपने सामाजिक जीवन

को त्याग दें। भारत जैसे देश में जहां शिक्षित बेरोजगारों की दर बहुत ज्यादा है, और जिन्हें रोजगार मिला भी हुआ है, उन्हें भी अपने श्रम के अनुकूल वेतन नहीं मिलता। एक आंकड़े के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगाररत लोगों में से 67 फीसद ऐसे हैं जो कार्य संबंधी कारणों से तनावग्रस्त रहते हैं जिससे उनके परिवारों में भी तनावग्रस्त वातावरण बन जाता है। तिस पर कार्यस्थलों का वातावरण उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील और समझदारी भरा न हो तो उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसे में उनसे सप्ताह में 90 घंटे कार्य करने की अपेक्षा करना उनकी सामाजिक और पारिवारिक जिंदगियों को नर्क में झोंक देने जैसा है। आजकल तो ऐसे भी संस्थान हैं जो अपने बड़े-बड़े अधिकारियों को ज्यादा वेतन इसलिए देते हैं कि वे छोटे कर्मचारियों का शोषण करें। वास्तव में बहस इस पर होनी चाहिए कि संस्थाओं में कर्मचारियों को उत्पादनक्षम वातावरण कैसे मिले जिससे पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन में संतुलन आए न कि उनसे 90 घंटे काम करने की अपेक्षा की जाए। हालांकि अब एल एंड टी की एचआर हेड ने अपने चेयरमैन का बचाव करते हुए कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है। लेकिन सच तो यह भी है कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।

कटाक्ष/ सहीराम

नब्बे घंटे काम

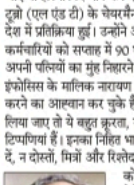

देखो जी, जब देश का प्रधानमंत्री सवा सौ घंटे काम करने वाला हो, तो कम से कम नब्बे घंटे काम करना तो प्रजा का भी बनता ही है न जी। वैसे, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि अभी उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। तो जब आप नब्बे घंटे काम करने लगेंगे तो मालिक लोग भी कह सकते हैं कि अभी आपकी क्षमताओं का पूरा उपयोग कहां हुआ है। देखिए जी, काम के घंटे बढ़ाने की मांग काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। अभी साल भर भी नहीं हुआ जब मांग थी सत्तर घंटे काम करने की। वह मांग नारायण मूर्ति जी ने की थी। अब नब्बे घंटे की मांग लेकर सुब्रमण्यम जी आ गए हैं। काम के घंटे बढ़ाने की शुरुआत कोरोना काल से हुई थी। तब भाजपा की राज्य सरकारों ने काम के घंटे आठ बढ़ा कर दस तक कर दिए थे। मतलब एक तरह से नारायण मूर्ति जी की मांग पूरी कर दी थी। कोरोना काल चलता रहता तो नब्बे घंटे काम वाली मांग अपने आप पूरी हो जाती। वैसे भी कोरोना काल तो मालिक लोगों के लिए स्वर्ण काल ही था न, जब मालिक लोगों को बिन मांगे ही सब कुछ मिल रहा था। बताते हैं कि उसी काल में अडानी जी की संपत्ति में जबर्दस्त उछाल आया था।

लेकिन जी, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि काम है कहां? बेरोजगारी तो सातवें आसमान पर है। ऐसे में घर में बैठ कर बीवी का मुंह ताकते रहने की बात तो तब आएगी न जी, जब कोई शादी-ब्याह का ढौल जमेगा। बिना काम के वह हो ही नहीं रही। आलम यह है कि युवा या तो रील बना कर या फिर रील देख कर अपना टाइम पास कर रहे हैं। हां, अलबत्ता यह बिल्कुल संभव है कि कम से कम नब्बे घंटे रील देखने का प्रचलन चल जाए। लेकिन बिना काम के नब्बे घंटे काम कैसे किया जाए। बड़ी समस्या पैदा हो गई है। सरकार स्कीमें भी ऐसी ही ला रही है न। अब देखिए, फौज में जाने वाले युवक पंद्रह-बीस साल नौकरी करके पेंशन पर आते थे। अब अग्निपथ स्कीम के चलते वह नौकरी भी चार साल की ही रह गई है। प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे भी हायर एंड फायर चल रहा है। इसलिए दो-चार हफ्ते नब्बे घंटे काम करने के बाद फिर काम ही न बचे तो? फिलहाल तो रील बनाओ और रील देखो। नब्बे घंटे का टारगेट तो इसी तरह से पूरा किया जा सकता है।

टमाटर और किसान एक भाव

सामयिक

पंकज चतुर्वेदी

झारखंड के लातेहार जिले में बालूमाथ और बारियातू के इलाके दो किस्म के टमाटर की खेती के लिए मशहूर हैं-एक है मोटे छिलके वाला गुलशन जिसका इस्तेमाल सब्जी विशेष तौर पर सलाद के रूप में किया जाता है। वहीं सलेक्शन नामक किस्म के टमाटर के छिलके की परत नरम होती है। इसका इस्तेमाल सब्जी, चटनी और टोमैटो कैचअप के लिए किया जाता है। कुछ साल पहले तक टमाटर की लाली यहां के किसानों के गालों पर भी लाली लाती थी, लेकिन इस साल हालत यह है कि फसल तो बंपर हुई लेकिन लागत तो दूर, तोड़ कर मंडी तक ले जाने की कीमत तक नहीं निकल रही। रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदग्गा में जिन किसानों ने टमाटर उगाए या फिर पत्ता या फूल गोभी या फिर पालक, वे ट्रैक्टर से रौंद कर अपनी खड़ी फसल खुद ही चौपट कर रहे हैं।

गोभी के दाम हैं दो से चार रुपये तो टमाटर के हैं दो रुपये। इतने में तुड़ाई भी निकलती है, फिर मंडी तक कौन ले जाए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के हरवाई गांव में सुर्ख लाल टमाटर की फसल पर रोटावेलर चला कर गेहूं बोए जा रहे हैं। यहां किसानों ने 15 हजार रुपये बीघा पर खेत किराये पर लिए, फिर टमाटर बोए। पिछले महीने तो 400 रुपये क्रेट (25 किलो) एक बार बिका। फिर दाम 60 से 100 रुपये क्रेट गिर गए। अब 30 रुपये क्रेट तुड़ाई, 15 रुपये मंडी के पल्लेदार को, फिर परिवहन। आखिर, किसान कितना घाटा सहे! मध्य प्रदेश के बड़वानी में टमाटर मवेशी खा रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास भले ही बाजार में टमाटर के दाम 40 रुपये किलो हों लेकिन टमाटर उगाने के लिए मशहूर देश के विभिन्न जिलों में टमाटर कूड़े में पड़ा है। छत्तीसगढ़ के टमाटर किसान तो जलवायु परिवर्तन की अजब मार झेल रहे हैं, और उन्हें फसल खेत में नष्ट करनी पड़ रही है। दुर्ग जिले में पहले तो चक्रवाती तूफान के चलते कोई 15 दिन बदली हुई, फिर अचानक जाड़ा बढ़ गया। इससे टमाटर तेजी से पकने लगे। जब पके टमाटर की आवक ज्यादा हुई तो दाम गिर गए। यहां प्रायः इतनी ठंड पड़ती नहीं। अब टमाटर समय से पहले पक रहे हैं, न तोड़ो तो गिर जाते हैं। मजबूर किसान फसल नष्ट कर रहा है।

पड़ोसी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हालात भी अलग नहीं हैं। यहां मेडक के शिवमपेट में टमाटर की तैयार फसल को आग लगाने की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। विदित हो टमाटर 15-27 डिग्री के बीच के तापमान में सबसे अच्छे से उगते हैं तथा इसके लिए माकूल औसत मासिक तापमान 21-23 होता है। 32 डिग्री से अधिक तापमान फल लगने और उसके विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दक्षिणी राज्यों में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित टमाटर की खेती में सफेद फंगस और पत्ती में छेद

करने वाले कीट की दिक्कत ने पहले से ही कीटनाशक का खर्च बढ़ाया था। फसल अच्छी हो गई तो बाजार में दाम नहीं मिलने से किसान कर्ज में दब गया। हालांकि न तो यह पहली बार हो रहा है, और न ही टमाटर के साथ हो रहा है।

उम्मीद से अधिक हुई फसल सुनहरे कल की उम्मीदों पर पानी फेर देती है-घर की नई छप्पर, बहन की शादी, माता-पिता की तीर्थ-यात्रा; न जाने ऐसे कितने ही सपने वे किसान सड़क पर 'कैश क्रॉप' कहलाने वाली फसल के साथ फेंक आते हैं। साथ होती है तो केवल एक चिंता-खेती के लिए बीज, खाद के लिए लिए गए कर्ज को कैसे उतारा जाए? पूरे देश की खेती-किसानी अनियोजित, शोषण की शिकार और किसान विरोधी है। तभी हर साल देश के कई हिस्सों में अफरात फसल को सड़क पर फेंकने और कुछ ही महीनों बाद उसी फसल के लिए त्राहि-त्राहि की घटनाएं होती रहती हैं। किसान मेहनत कर सकता है, अच्छी फसल दे सकता है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को भी उसके परिश्रम के माकूल दाम, अधिक माल के सुरक्षित भंडारण के बारे में सोचना चाहिए। हर दूसरे-तीसरे साल कर्नाटक में कई जिलों के किसान अपने तीखे स्वाद के लिए मशहूर हरी मिर्च को सड़क पर लावारिस फेंक कर अपनी हताशा का प्रदर्शन करते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में कभी टमाटर तो कभी अंगूर, कभी मूंगफली तो कभी गोभी किसानों को ऐसे ही हताश करती है। दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आए साल आलू की टनों फसल बगैर उखाड़े मवेशियों को चराने की घटनाएं सुनाई देती हैं।

> उम्मीद से अधिक फसल सुनहरे कल की उम्मीदों पर पानी फेर देती है-घर की नई छप्पर, बहन की शादी, माता-पिता की तीर्थ-यात्रा: न जाने ऐसे कितने ही सपने वे किसान सड़क पर 'कैश क्रॉप' कहलाने वाली फसल के साथ फेंक आते हैं। साथ होती है तो केवल एक चिंता-खेती के लिए बीज, खाद के लिए लिए गए कर्ज को कैसे उतारा जाए? पूरे देश की खेती-किसानी अनियोजित, शोषण की शिकार और किसान विरोधी है, और किसान पस्त है

आश्चर्य इस बात का होता है कि जब हताश किसान अपने ही हाथों अपनी मेहनत को चौपट कर रहा होता है, तो गाजियाबाद, नोएडा, या दिल्ली में आलू के दाम पहले की ही तरह तने दिखते हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में जब टमाटर मारा-मारा घूमता है तभी वहां से कुछ किमी. दूर गुजरात में लाल टमाटर के दाम ग्राहकों को लाल किए रहते हैं। सरकारी और निजी कंपनियां सपने दिखा कर ज्यादा फसल देने वाले बीजों को बेचती हैं, जब फसल बेहतरीन होती है तो दाम इतने कम मिलते हैं कि लागत भी न निकले। दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश में कृषि उत्पाद के न्यूनतम मूल्य, उत्पाद खरीदी, बिचौलियों की भूमिका, किसान को भंडारण का हक, फसल-प्रबंधन जैसे मुद्दे गौण दिखते हैं, और यह हमारे लोकतंत्र की आम आदमी के प्रति संवेदनहीनता का प्रमाण है। सब्जी, फल और दूसरी कैश-क्रॉप को बगैर सोचे-समझे प्रोत्साहित करने के दुष्परिणाम दाल, तेल-बीजों (तिलहनों) और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में संकट की सीमा तक कमी के रूप में सामने आ रहे हैं।

किसानों के सपनों की फसल को बचाने के दो तरीके हैं। एक, जिला स्तर पर अधिक से अधिक कोल्ड स्टोरेज हों और दूसरा, स्थानीय उत्पाद के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण खोले जाएं। देश में इस समय अंदाजन आठ हजार कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1817, गुजरात में 827, पंजाब में 430 हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पर आलू और प्याज का कब्जा होता है। जरूरी है कि खेती में कौन सी फसल और कितनी उगाई जाए, उसकी स्थानीय मांग कितनी है, और कितने का परिवहन संभव है -इस बाबत नीतियां तालुका या जनपद स्तर पर ही बनें तो पैदा फसल के एक-एक कतरे के श्रम का सही मूल्यांकन हो सकेगा। एक बात और, कोल्ड स्टोरेज या वेअरहाउस पर किसान का नियंत्रण हो, न कि व्यापारी का कब्जा।

(लेख में विचार निजी हैं)

चीन के साथ सीमा खासकर लद्दाख से सटी सीमा पर तमाम दावों के बावजूद सैन्य तनाव कम नहीं हुआ है। इस बीच, सेना प्रमुख ने कहा है, 'सर्दियों में हम भारत-तिब्बत सीमा पर भी सैनिकों की तैनाती में कमी नहीं कर रहे।'

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

काम के घंटे घटाना वक्त की मांग

मुद्दा

कुमार समीर

इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति ने एक साल पहले युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी और अब निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) के अध्यक्ष एस. एन. सुब्रमण्यम ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि कामगारों को हफ्ते में 90 घंटे काम करने को तैयार रहना चाहिए। इतने पर ही नहीं रुके, आगे कहा कि एक्स्ट्रा रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा काम करना होगा और इसके लिए रविवार को भी काम करना चाहिए। आखिर, घर में रह कर मजदूर बीवी का मुंह कितनी देर तक निहारते रहेंगे। अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी ने भी उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर काम ही नहीं रहा तो बीवी घर से भाग जाएगी और फिर क्या होगा?

एल एंड टी के चेयरमैन के बयान के बाद देश में फिर से मजदूरों के काम के घंटे को लेकर बहस शुरू हो गई है। कॉरपोरेट जगत के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है। आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन हर्ष गोयनका ने एल एंड टी चेयरमैन के बयान की आलोचना करते हुए कहा, एक हफ्ते में 90 घंटे काम? रविवार को 'सन-ड्यूटी' क्यों न कहा जाए और 'छुट्टी' को एक मिथकीय अवधारणा क्यों न बना दिया जाए! वर्क-लाइफ बैलेंस वैकल्पिक नहीं, बल्कि जरूरी है। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब भारत में पहले से ही लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो क्यों कामगारों के घंटे बढ़ाने की बात उठती रहती है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय सबसे ज्यादा काम करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति सप्ताह 46.7 घंटे, चीन में 46.01, ब्राजील में 39, अमेरिका में 38, जापान में 36.6, इटली में 36.3, ब्रिटेन में 35.5, फ्रांस में 35.9, जर्मनी में 34.2 और कनाडा में 32.5 घंटे मजदूरों से काम कराया जाता है। इन आंकड़ों के बावजूद भारत में काम के घंटे बढ़ाने के लिए जब-तब शिगूफा छोड़ा जाता रहा है।

सच तो यह है कि पूरी बहस को इसलिए संचालित किया जा रहा है ताकि मोदी सरकार द्वारा मार्च, 2025 में लाए जाने वाले लेबर कोड, जिसमें काम के घंटे 12 कर दिए जाने हैं, की सामाजिक स्वीकृति हासिल की जा सके। इसके लिए बीच-बीच में इस तरह की चर्चाएं शुरू करवाने का ताना-बाना बुना जाता है। सच तो यह है कि दुनिया में

काम के घंटे बढ़ाने के तर्कों के विरुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दौर में काम के घंटे कम करने की कवायद-कार्रवाई हो रही है। तमाम देशों में सप्ताह में चार दिन काम की पद्धति शुरू हुई है। जूम के मालिक एरिक युवान जैसे एआई इनोवेटर्स का मानना है कि एआई हर कंपनी के लिए चार दिन का कार्यसप्ताह हासिल करने की कुंजी होगा। उनके अनुसार चार दिन के वर्किंग में 92 प्रतिशत की सफलता दर है। जापान जैसे देशों में काम के घंटे लगातार कम किए जा रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां जापान में वर्ष 2000 में 1839 घंटे सालाना काम के थे वहीं उसे 2022 में घटा कर 1629 घंटे सालाना कर दिया गया। इससे लगभग वार्षिक काम के घंटे में 11.6 प्रतिशत की गिरावट आई। बेल्जियम, आइसलैंड, यूएई, स्पेन और नीदरलैंड जैसे देशों में चार दिन के कार्य दिवस सप्ताह में कर दिए गए हैं। जापान की रिक्रूट वर्क्स इंस्टिट्यूट के विश्लेषक ताकाशी सकामोटो के निष्कर्ष के अनुसार, देश में अब कई यूरोपीय देशों की तरह काम के घंटे कम किए जा रहे हैं।

ऑटोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ब्रिटेन में 88 प्रतिशत कंपनियां अपने कर्मचारियों के काम के घंटे 10 प्रतिशत तक कम कर रही हैं यानी कुल मिला कर कहा जाए तो दुनिया में काम के घंटे कम करने की दिशा में काम हो रहा है वहीं भारत, जहां पहले से ही काम के घंटे ज्यादा हैं, में उन्हें बढ़ाने की वकालत की जा रही है। दरअसल, देश में भीषण बेरोजगारी और महंगाई में मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा कर काम के घंटे 12 करने का कानून बनाया जा रहा है। दुखद यह है कि इस सबसे उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। संवैधानिक दृष्टि से देखें तो काम के घंटे बढ़ाने को जो कुछ भी किया जा रहा है, वह स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 42 और 43 का उल्लंघन है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है, जिसकी मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्वों में व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 42 जहां काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं के लिए राज्य की जवाबदेही तय करता है वहीं अनुच्छेद 43 मजदूरों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दौर में जब दुनिया बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के खतरे को महसूस कर रही है, तब भारत में काम के घंटे बढ़ाने के कारण बेरोजगारी और भी बढ़ेगी, यह तय है।

आत्मसंयम | डॉ. ज्ञानानंद दास

शास्त्रों में वाह्य भोग, जिन्हें हम पांच इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, को विषय कहा गया है अर्थात विषय वे बाहरी आकर्षण हैं जो हमारी इंद्रियों को खींचते हैं, और हमारे मन और शरीर पर प्रभाव डालते हैं। विषय का जोर ही इंद्रियों को सक्रिय करता है और उन्हें वश में कर लेता है। मनुष्य की पञ्च इंद्रियां विषय में कैसे फंस जाती हैं? इसे गीता में समझाया गया है। कृष्ण भगवान कहते हैं-'कोई नाव पानी में चल रही हो और अचानक तूफान आ जाए तो हवा की गति के कारण नाव को हवा अपनी ओर खींचने लगती है। इसी प्रकार ये इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं।' इस प्रकार, हम विवश हो जाते हैं। रामायण का बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि भगवान श्री राम जब किष्किंधा पहुंचते हैं तो बाली और सुग्रीव के बीच झगड़े में सुग्रीव को बाली के खतरे से बचा लेते हैं। उस समय सुग्रीव सीता की खोज में मदद करने का वादा करते हैं, और राम उन्हें किष्किंधा का राजा बना देते हैं। राजा बनते ही सुग्रीव भोग-आनंद में रमण करने लगे। एक राजा के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांच विषयों को प्राप्त करना बिल्कुल स्वाभाविक है! सुग्रीव भी उन सब विषयों से बंध गए और वचन भूल गए। जैसे ही नाव हवा के वेग से उस ओर खिंची चली जाती है, सुग्रीव विषय के वेग में भगवान का वचन भूल गए और विषयों से बंध गए। श्रीराम ने लक्ष्मण को जाकर सुग्रीव से मिलने को कहा। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर धनुष उठा लिया और सुग्रीव भयभीत होकर पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हुए। यहां इंद्रियों की प्रचंड आकर्षण शक्ति का वर्णन किया गया है, और दिखाया गया है कि किस प्रकार इंद्रियों का बंधन भगवान के वचन को भी भुला देता है। हां, विषयों की ओर दौड़ते इन इंद्रियों के घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए भगवान स्वामिनारायण वचनामृत में बताते हैं-'वैराग्य, स्वधर्म, तप और नियम पालन के साधनों को करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और अंततः मन पर विजय प्राप्त की जाती है।' जगत के राग, भोग और विषय अपने आकर्षण से हमें विवश कर देते हैं। इंद्रियां अपनी स्वाभाविकता के कारण उन विषयों के प्रति हार जाती हैं। इसे रोकना ही आत्मसंयम है।

रीडर्स मेल

बातचीत के अलावा विकल्प नहीं

शेख हसीना के पद से हटने और उनके भारत आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। तारबंदी का यह ताजा मुद्दा है, इस पर यह साफ समझने की जरूरत है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, बल्कि सीमा सुरक्षा की वजह से यह दोनों देशों के बीच पहले से तय है। न केवल बांग्लादेश इस छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है, बल्कि वहां रह रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भी बांग्लादेश ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है, यह अत्यंत दुखद है। चीन और पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का भी शत्रुतापूर्ण और विरोधी रवैया निस्संदेह भारत के लिए खतरे की घंटी है, और बांग्लादेश ने जिस तरह पाकिस्तानियों को अपने यहां आसानी से प्रवेश देना शुरू किया है तो यह भी संभव है कि बांग्लादेश के रास्ते से आतंकी भारत में प्रवेश करें। तो इन सब बातों से कसैलापन तो बढ़ेगा ही, काम भी नहीं होगा। उसके लिए तो आपस में बातचीत करके ही कुछ हल निकाला जा सकता है। बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

बाल गोविंद, नोएडा

विश्व बंधुत्व का पैरोकार भारत

आस्था के महान और विश्व के विशालतम और भव्य आयोजन का सिरमौर महाकुंभ जैसे ही आरंभ हुआ देश एवं विश्व को अद्भुत और अलौकिक दृश्यों का अवलोकन एवं साक्षात्कार होना शुरू हो गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई से उत्तीर्ण होने के बाद एक श्रद्धालु के साक्षात्कार से पता चला कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो एकमात्र रास्ता अध्यात्म ही है, अनेकों आदि ऋषियों का नाम लेते हुए इस भक्त ने भारत के ज्ञान और दर्शन एवं अतीत के अनुसंधानों का भी उल्लेख किया, साथ ही भारतीय ज्ञान और दर्शन की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका समेत विश्व के विभिन्न देशों से आए श्रद्धालुओं ने भी अपने-अपने तर्क दिए और आध्यात्मिक ज्ञान का हृदय भारत को बताया। विश्व का भारत के प्रति ऐसा आकर्षण और स्वीकारोक्ति दर्शाती है कि भारत वास्तविक रूप से विश्व बंधुत्व का सशक्त पैरोकार बन सकता है।

मनोज पुरुषार्थी, मेरठ

भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती

तिरुपति मंदिर जैसे हादसे हमारे देश में कई धर्म स्थलों पर पहले भी हो चुके हैं। भीड़ की स्थिति में बीमारों, बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांगों एवं महिलाओं को बाहर जाने से परहेज करना चाहिए। भीड़ में धैर्य और सबूरी के साथ-अपनी बारी का इंतजार करने व्यवस्था बनी रहती है। मंदिर मैनेजमेंट समिति एवं स्थानीय प्रशासन को भी बढ़ती भीड़ के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों एवं मंदिरों में अगर सभी लोग नियमों एवं अनुशासन का पालन करें तो अप्रिय हादसों से बचा जा सकता है। प्रयागराज में संगम पर महाकुंभ आरंभ हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक, इसमें 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे। इतनी भीड़ बल्कि कहा जाए कि महाभीड़ का व्यवस्थापन बड़ी चुनौती है। शासन-प्रशासन को इस कार्य में जनसहयोग मिलना जरूरी है।

ललित महालकरी, इंदौर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 150
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सहारा स्टार, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR/GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान 1936

मेटा की माफी

मेटा इंडिया कंपनी को अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के एक बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी है, तो यह जरूरी भी था और स्वागतयोग्य भी है। पिछले सप्ताह फेसबुक के मालिक के नाते ख्यात मार्क जुकरबर्ग ने यह कह दिया था कि कोविड-19 के चलते भारत सहित ज्यादातर देशों में सरकारों को हार का मुंह देखना पड़ा। इस बयान की भारत में तीखी आलोचना हो रही थी कि जुकरबर्ग ने गलत बयानी की है। भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन को जीत मिली है और वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं। भारत की आपत्ति के बाद जुकरबर्ग ने स्वयं तो नहीं, पर उनकी कंपनी मेटा ने माफी मांगते हुए इसे 'अनजाने में हुई गलती' कहा है। क्या यह मान लिया जाए कि यह गलती अनजाने में हुई है? क्या विशाल सोशल मीडिया मंच फेसबुक को संभालने वाली इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को यह शोभा देता है कि वह भारत जैसे देश के चुनाव परिणाम से परिचित न हों? अगर यह गलती जुकरबर्ग से अनायास या अनजाने में हुई है, तो भी यह गंभीर बात है। यह बात तो साफ है कि वह भारत को लेकर सजग नहीं हैं।

मेटा इंडिया भी जुकरबर्ग की ही कंपनी है, जिसके एक आला अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह मेटा के लिए भारत एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण देश बना हुआ है।

अगर मेटा कंपनी के लिए भारत खास है, तो उसके मालिक मार्क जुकरबर्ग को इसका नाम बहुत संभलकर लेना चाहिए और किसी भी झूठे प्रचार से बचना चाहिए।

अगर मेटा के लिए भारत खास है, तो इसके मालिक को भारत का नाम बहुत संभलकर लेना चाहिए। वैसे भी भारत सरकार अमेरिका, यूरोपीय देशों या चीन की तरह आक्रामक नहीं है। आक्रामक देशों में तो सरकारें फेसबुक या मेटा की गलतियों पर चारों ओर से टूट पड़ती हैं। कई बार ऐसी गलतियों के चलते कंपनियों को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। उन देशों की कड़ाई का ही नतीजा है कि सोशल मीडिया कंपनियां इन देशों में बहुत सजग रहती हैं, जबकि भारत के मामले में उनकी नीति बदल जाती है। भारत की उदारता का ये कंपनियां अधिकतम दुरुपयोग करना चाहती हैं। जुकरबर्ग से जुड़े ताजा मामले को एक सबक के रूप में लेना चाहिए। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों को साफ शब्दों में सचेत कर देना चाहिए कि वे भारत के महत्व को समझें व पर्याप्त सजग रहें। भारतीयों को पता है कि साल 2019 में अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन ने उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए फेसबुक पर पांच अरब डॉलर का जुर्माना लगाया था। कोई दोराय नहीं कि ऐसी कंपनियों पर कड़ी नजर रखना समय की मांग है।

एक खास बात यह है कि फेसबुक के मालिक को स्वयं ही गलत दावे करते या गलत बयानी करते देखा गया है। इसका दूसरों पर क्या असर होगा? फेसबुक या अन्य सोशल मंचों पर बहुत सारी फेक या फर्जी सूचनाएं तैरती रहती हैं और भारत में तो शायद कुछ ज्यादा ही मनगढ़ंत या झूठी सूचनाओं का प्रचार-संचार होता है। सूचनाओं की सच्चाई के प्रति जिम्मेदारी का भाव सभी में होना चाहिए। एक आम नागरिक को भी सजग रहना चाहिए कि उसके मार्फत कोई गलत सूचना संचारित-प्रसारित न हो और जुकरबर्ग जैसे मालिकों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन चल रहे सोशल मीडिया मंचों पर किसी झूठ का सिक्का न चले। सूचनाओं की सच्चाई के प्रति सभी को गंभीर होना चाहिए और झूठ फैलाने वाले लोगों से हर स्तर पर बचने की जरूरत है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 16 जनवरी, 1950

सम्मेलन की प्राप्ति

गत सप्ताह की प्रमुख घटना राष्ट्रमंडलीय देशों के विदेश मंत्रियों का वह महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो कि विश्व की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए ९ जनवरी को कोलम्बो में आरंभ हुआ था और ६ दिन तक दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं, हिन्दचीन, बर्मा और मलाया की स्थिति, सुदूर पूर्व की अवस्था, साम्यवादी चीन की मान्यता तथा उसके साथ राष्ट्रमंडलीय देशों के भावी संबंध, यूरोप एवं मध्यपूर्व की राजनैतिक स्थिति तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के डालर निर्यात की वर्तमान व भावी अवस्थाओं आदि सामान्य हित के विभिन्न प्रश्नों का सिंहावलोकन करने के पश्चात् १४ जनवरी को समाप्त हो गया। सम्मेलन के अन्त में अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति से पता चलता है कि विश्व की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के संबंध में राष्ट्रमंडल के समस्त सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने बहस करते हुए एकता की भावना का परिचय दिया। स्वभावतः यह आशा नहीं की जा सकती थी कि प्रत्येक प्रश्न पर सबका एक ही दृष्टिकोण हो, लेकिन इस प्रकार के सम्मेलन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का अच्छा अवसर उपस्थित करते हैं, जैसा कि सम्मेलन के अन्त में नेहरूजी ने कहा भी, "हमने उद्देश्यपूर्ण ढंग से समस्याओं पर विचार किया है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न किया है। विविध भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली जनता के प्रतिनिधियों के लिए यह एक बड़ी सफलता है।"

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि विचाराधीन प्रश्नों पर नेहरू जी ने निर्भीकतापूर्वक सम्मेलन के सम्मुख अपना प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और सम्मेलन उससे अत्यधिक प्रभावित भी हुआ, जिसका संकेत अधिकृत विज्ञप्ति से भी मिलता है- "इस क्षेत्र में प्रगतिशील नीतियों को अपनाने से शांति स्थापित करने में तथा लोगों की खुशहाली के लिए जो महान सफलता प्राप्त की जा सकती है, उससे सम्मेलन प्रभावित हुआ।" सम्मेलन ने सर्वसम्मत निश्चय किया कि इस क्षेत्र में जो परिवर्तन हो चुके हैं, उन्हें देखते हुए उन्नति तभी हो सकती है जबकि इधर के लोगों की आर्थिक अवस्था में सुधार किया जाये। इस निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सम्मेलन ने प्रस्ताव किया है कि राष्ट्रमंडलीय देशों की एक परामर्श समिति नियुक्त की जाये।

ब्रह्मपुत्र पर न बने मनमानी का बांध

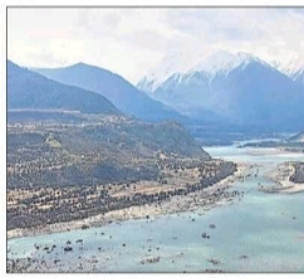

बीजिंग द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर बनाया जाने वाला सबसे बड़ा बांध दक्षिण एशिया के देशों के लिए कहीं जहर न बन जाए। समस्या बढ़ने से पहले समाधान खोजना होगा।

यहां स्कैन करें

निम्मी कुरियन | प्रोफेसर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च

भारत और चीन के बीच भू-राजनीतिक तनाव का नया केंद्र तिब्बत के मेडोग काउंटी की विशाल घाटी में तैयार होता दिख रहा है। यहां यारलुंग त्सांगपो अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले यू-टर्न लेती है। यहां विशाल जलराशि का तीव्र वेग देखा जाता है, यहीं चीन दुनिया की सबसे बड़ी पन-बिजली परियोजना का विकास करना चाहता है। यहां चीन प्रति घंटे 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा करेगा और इस संयंत्र की कुल क्षमता 60,000 मेगावाट होगी। इसके लिए वह 137 अरब डॉलर खर्च करने को तैयार है। इस परियोजना का सीधा असर भारत और बांग्लादेश में उन लोगों पर पड़ेगा, जो इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में रहते हैं। जाहिर है, चीन की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या तरल सोने के लिए चीन की खोज दक्षिण एशिया के लिए जहर का प्याला साबित होगी?

तिब्बत एशिया की कई शक्तिशाली नदियों का स्रोत है। ये नदियां एशिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में बहती हैं। यह स्पष्ट है कि चीन तिब्बतीय क्षेत्र में बहुत तेजी से आर्थिक गतिविधियां चला रहा है। विकास की गतिविधियों के चलते तिब्बत साल 2000 के बाद से ही भारी दबाव का सामना कर रहा है। आर्थिक गतिविधियों के चलते वनों की कटाई, मिट्टी का क्षरण, भूस्खलन, बाढ़, अम्लीय वर्षा और प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन जल स्रोतों की स्थिति दिनों-दिन दुर्बल भी होती जा रही है। इस पूरे क्षेत्र में अनेक तरह की समस्याएं सामने आई हैं। चीन अपने तेज विकास से पसरता चला जा रहा है और अपनी सीमा के पार भी उसका प्रभाव फैलता जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में पानी पर भारत-चीन के बीच बातचीत सतही तौर पर ही चलती रही है। यह बातचीत विवाद के अंतिम समाधान तक पहुंचने में असमर्थ और अक्सर अनिच्छुक भी रही है। समय-समय पर होने वाले गतिरोधों और शत्रुता के इतिहास के चलते भी समाधान की इच्छा का अभाव रहा है। दोनों देशों के बीच विवादों का पुख्ता समाधान लक्ष्य भी नहीं है, इसलिए भी बातचीत के नतीजे बहुत मामूली निकलते हैं। हिमालयी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका भी वास्तविक कम, और प्रतीकात्मक ज्यादा रही है। यही वजह है कि भारत, चीन, नेपाल इत्यादि क्षेत्रों में विवाद बढ़ रहे हैं।

एक कड़वा सबक भारत ने 2017 में कीमत चुकाकर सीखा था, जब चीन ने भारत के साथ हाइड्रोलॉजिकल डाटा साझा करने से इनकार कर दिया, पर बांग्लादेश के साथ डाटा साझा करने के लिए वह आगे बढ़ा। भारत-चीन गतिरोध की पृष्ठभूमि में ही डोकलाम में झड़प हुई, जवान शहीद हुए। हर बार चीन हावी दिखा।

जल-सुरक्षा के संबंध में भारत की नीति लचीली रही है, जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचा है। बहुत सुरक्षित ढंग से चलने की परंपरा के चलते दोटूक संवाद की संभावना नहीं बन पा रही है। नतीजतन, हमने चीन के सामने हमेशा अपनी न्यूनतम मांगें रखी हैं, जिसके चलते चीन को खुली छूट मिल गई है। वह अपने निचले इलाकों या पड़ोसियों की चिंता के प्रति किसी भी जवाबदेही के बिना आगे बढ़ रहा है। सुधार की उम्मीद कम होती जा रही है। इसका एक कारण यह भी है कि चीनी दृष्टिकोण मैकेनिकल है, वह हर बात में सौदेबाजी को तरजीह देता है। तिब्बत स्थित तीन स्टेशनों से बाढ़ के मौसम में हाइड्रोलॉजिकल डाटा पाने के लिए भारत सालाना 82 लाख रुपये का भुगतान करता है।

ब्रह्मपुत्र के बारे में भी चीन केवल एकआयामी अध्ययन कर रहा है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पानी की गुणवत्ता के गंभीर मुद्दे से भी ध्यान हट गया है। ऐसी ही निष्क्रियता की कीमत 2017 में सामने आई थी, जब ब्रह्मपुत्र का पानी काला हो गया था। जल प्रदूषण का स्तर कथित तौर पर 1,249 एनटीयू हो गया था, जो सुरक्षित सीमा से 250 गुना अधिक था।

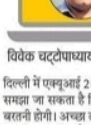

विशेष चिंता का विषय तीन नदियों का क्षेत्र है, जिसमें मध्य तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो, ल्हासा नदी और न्यांगचू बेसिन शामिल हैं, यह क्षेत्र पर्यावरणीय गिरावट का भी सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक दोहन वाले क्षेत्रों में से एक ग्यामा घाटी भी स्थित है, जहां तांबा, मोलिब्डेनम, सोना, चांदी, सीसा और जस्ता के भंडार हैं। चीनी वैज्ञानिकों के अध्ययन ने भी यहां नदियों की धारा के तलछट और अवशेषों में भारी धातुओं की उच्च सामग्री की आशंका की ओर इशारा किया है। जाहिर है, जब पानी बढ़ेगा और चीन पानी छोड़ेगा, तो तलछट व अवशेषों को बहकर नीचे आने का रास्ता मिल जाएगा। पूरे हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बांध-निर्माण परियोजनाओं की वजह से तलछट में जमा कचरा या संचयी प्रभाव के बारे में भी बड़े सवाल उठते हैं।

ध्यान देने की बात है कि हिमालय क्षेत्र में भूगर्भीय गतिशीलता भी ज्यादा है, भूकंप एक हमेशा मौजूद रहने वाला खतरा है। खुद चीनी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है और पाया है कि पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में साल 2008 में जो भूकंप आया था, जिसमें 80,000 लोग मरे थे, जिपिंगपु बांध को भी नुकसान पहुंचा था।

पिछले हफ्ते तिब्बत में शिगात्से के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप चीन को याद दिलाता है कि अब बांध निर्माण न तो लागत-मुक्त है और न किसी समस्या का रामबाण है। ऐसे बांधों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बीजिंग को विचार करना चाहिए कि ऐसे बांध के क्या जोखिम हैं, इसकी पर्यावरणीय लागत कितनी है, इसे लेकर क्षेत्रीय या वैश्विक भावनाओं का क्या स्वरूप है?

सवाल यह भी है कि ब्रह्मपुत्र के तटवर्ती देश क्या वैश्विक स्तर पर किसी मिसाल से सीख सकते हैं? चाहे वह उत्तरी अमेरिका में 1909 का ऐतिहासिक ग्रेट लेक्स समझौता हो या दक्षिण-पूर्वी यूरोप में 2005 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय सावा नदी बेसिन आयोग हो। नदी जल समाधान के ये समृद्ध साक्ष्य हमें बताते हैं कि तटवर्ती देशों के बीच विश्वास और सहयोग को आदत में ढालने में समय लगता है। कैटामायो-चिरा, जारुमिला, पुयांगो-टुम्बेस जल क्षेत्र की संयुक्त रूप से रक्षा करने के लिए 2023 में हुए इक्वाडोर-पेरू समझौते से पता चलता है, परस्पर सहयोग के लंबे प्रयासों के बाद ही ऐसा समझौता संभव होता है। ऊपर किसी जगह पर बांध बनाने से पहले नीचे के देशों के जन-जीवन, खेती और खेतिहर लोगों का भविष्य भी देखना चाहिए। क्या अभी प्रभावित होने वाले लोगों का व्यापक हित देखा जा रहा है?

व्यापक सुरक्षा से जुड़े ब्रह्मपुत्र विमर्श पर तमाम उदाहरणों से सबक लेते हुए बहुत सोच-विचार के साथ चलना होगा। लापता जल एजेंडे को आवाज देने और पूरे दिल से अपना हित देखने की जरूरत है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

घने कोहरे और जहरीली धुंध का कैसे किया जाए इलाज

यहां स्कैन करें

विवेक चट्टोपाध्याय | प्रिंसिपल प्रोग्राम मैनेजर, सीएसई

बुधवार को कमोबेश पूरे दिन उत्तर भारत कोहरे की गिरफ्त में रहा। सुबह के वक्त दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में दृश्यता शून्य के करीब थी, जिसका खासा असर रेल और हवाई सेवाओं पर पड़ा। दिल्ली आने वाली 25 से अधिक ट्रेनों व 184 से ज्यादा विमानों पर इस कोहरे की मार पड़ी और उनके परिचालन में देरी देखी गई। इन दिनों सूरज की किरणें नीचे तक नहीं आ रहीं और मौसम भी शीतलहर का है, इसलिए 'स्मॉग' बन रहा है। लग रहा है कि जमीन के बिल्कुल करीब बादल तैर रहे हैं। कई वजहों से यह स्थिति सुखद नहीं कही जाएगी।

मौसम का यह मिजाज इसलिए है, क्योंकि कुहासा और प्रदूषण का संयोग बन गया है। वैज्ञानिक शब्दावली में इसे ही 'स्मॉग' कहते हैं। आमतौर पर शहरी इलाकों में अब स्मॉग ही दिखता है, ग्रामीण भारत में 'फॉग' देखे जा सकते हैं। दरअसल, होता यह है कि फॉग किसी भी पार्टिकुलेट मैटर (पीएम, यानी अतिसूक्ष्म कणों) पर चिपक जाता है और हवा में नमी अधिक होने के कारण वह जमीन के आसपास ठहरने लगता है। चूंकि मौसम में गर्माहट नहीं होती, इसलिए नीचे की ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर नहीं उठ पाती और प्रदूषण गहराने लगता है। दिक्कत यह है कि हम शहरी प्रदूषण की मूल वजहों पर बात ही नहीं करना चाहते और किसानों के पराली जलाने पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, जबकि शहरों का आंतरिक प्रदूषण स्मॉग के लिए मूलतः जिम्मेदार है। आंकड़े बताते हैं, साल 1996 में दिल्ली में 25 लाख गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती थीं, जिनकी संख्या 2023 तक बढ़कर 1.2 करोड़ हो गई। दिल्ली में कोहरे की आवृत्ति दर बढ़ गई है और अध्ययन बताते हैं कि 1989 से 2005 के दरम्यान यहां शीतलहर के दौरान अधिकतम तापमान में औसतन दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में कोहरे के घंटों में रोजाना औसतन आठ घंटे की वृद्धि हुई।

स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही हमें किसी स्वच्छ वायु अभियान की जरूरत है, जो चंद महीने नहीं, बल्कि साल भर चलता रहे।

देश का आर्थिक विकास इस मौसम से खासा प्रभावित होता है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्ग इस समय ज्यादा परेशान होते हैं। लिहाजा, सांस संबंधी रोगों के मरीजों और दिल के रोगियों को इन दिनों अपनी सेहत संभालनी पड़ेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से ऊपर है, तो हमारा स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, जबकि बुधवार को ही दिल्ली में एक्यूआई 200 के ऊपर बना हुआ था। इससे समझा जा सकता है कि हमें किस कदर की सावधानी बरतनी होगी। अच्छा तो यही होगा कि हम जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। स्कूलों ने तो ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, दफ्तरों को भी इन दिनों 'वर्क फ्रॉम होम' की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर भी घर से बाहर निकलने की अनिवार्यता है, तो हमें एन95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। यातायात के लिहाज से गाड़ियों को फॉग लाइट लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम हादसों को जन्म देते हैं। राजमार्गों पर ऐसी चेतावनी प्रणाली लगानी चाहिए, जो लोगों को घने कोहरे में सुरक्षित यात्रा की जानकारी दे।

वास्तव में, हम फॉग से नहीं निपट सकते, लेकिन स्मॉग से पार पा सकते हैं। हमारे पास अब ऐसे कई साधन उपलब्ध हैं, जिनसे अगले पांच या दस दिनों के मौसम का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रदूषण कम करने के लिए किस तरह के उपाय अपनाए जाने चाहिए, इसको लेकर हम उदासीनता बरतते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विडंबना देखिए कि किसी भी दल ने प्रदूषण को मुद्दा नहीं बनाया है, जबकि यही प्रदूषण स्मॉग के रूप में पूरी दिल्ली में पसरा हुआ है। कहने के लिए सरकारें ग्रैप लगा देती हैं, लेकिन जिस तरह की सख्ती की दरकार है, वह नहीं दिखातीं। प्रदूषण को लेकर हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए, जो पूरे साल अमल में लाई जाए। स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही हमें किसी स्वच्छ वायु अभियान की जरूरत है। वैसे भी, जब बीजिंग अपने यहां प्रदूषण को कम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? उम्मीद यही है कि भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर जारी 'मौसम विभाग विजन 2047' और 'मिशन मौसम' का शुभारंभ जलवायु के संदर्भ में एक स्मार्ट राष्ट्र बनाने का आधार बनेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आलोचकों से क्या डरना

मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, जो संतों की समाधियों, पीरों की मजारों, पवित्र नदियों, चमत्कारों या भूत-प्रेतों की खोज में भागता फिरूं। मेरे लिए तीर्थयात्रा करना जश्न मनाने सरीखा है। मेरे पिता और बहन की मृत्यु कम उम्र में ही गर्मी से हो गई थी और मुझसे भी गर्मी बहुत बर्दाश्त नहीं होती। शायद मुझे भी यह दुनिया जल्दी छोड़नी पड़ जाए, इसलिए मुझे इसके बारे में जितना संभव हो, उतना जानना होगा और उन खुशियों का आनंद उठाना होगा, जिनका मैं हकदार हूं।

जब मेरी मां ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब मैंने खुद से यह वादा किया था कि मैं हर सुबह खुश जगा करूंगा। भविष्य की ओर देखूंगा, लेकिन उसके लिए कभी वर्तमान का बलिदान नहीं दूंगा। मेरे जीवन के रास्ते में जहां से भी मुझे प्यास और अपनापन मिलेगा, उसे भरपूर बटोरूंगा। मुझे जो वक्त हासिल है, उसके पल-पल को जीभर जिऊंगा और ऐसी किसी भी चीज को कभी भविष्य के लिए नहीं टालूंगा, जो मुझे खुश कर सकती है।

मुझे सन् 1986 याद है, जब मैं भी सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी बदलने की यात्रा पर निकल पड़ा था। उस समय कई लोगों ने मेरी आलोचना की। उनकी निगाह में मेरा वह कदम एक पागलपन था, एकमात्र मेरी पत्नी ऐसी व्यक्ति थीं, जिन्होंने मुझे वह समर्थन दिया, जिसकी मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। उस समय कनाडा मूल की एक लड़की ने मुझसे कहा था कि उसके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ, और उसने मुझे एक पाठ्य सामग्री दी, जो वह अपने साथ लेकर आई थी। उसने कहा था, 'यह अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के उस भाषण का अंश है, जो उन्होंने 23 अप्रैल, 1910 को पेरिस के सोरबोन में दिया था।'

मैंने फौरन उस अंश को पढ़ा, जो उन पन्नों पर दर्ज था। बकौल रूजवेल्ट, 'आलोचक कुछ नहीं कहते, वे बस आरोप लगाने वाली अपनी उंगली उस वक्त उठा देते हैं, जब किसी ताकतवर को शिकस्त का सामना करना पड़ता है या जब वह कोई गलती कर बैठता है। असली श्रेय तो उनको ही जाता है, जो मैदान में होते हैं, जिनके चेहरे धूल, पसीने और खून से सने हुए होते हैं

असली श्रेय तो उसी व्यक्ति को जाता है, जो गलतियां करता है, जो नाकाम होता है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें दुरुस्त कर लेता है, क्योंकि गलतियों के बिना तो कोई प्रयास ही नहीं होता।

और जो बहादुरी से जंग लड़ रहे होते हैं... असली श्रेय उसे ही जाता है, जो गलतियां करता है, जो नाकाम होता है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें दुरुस्त कर लेता है, क्योंकि गलतियों के बिना तो कोई प्रयास ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक उत्साह और गहरी भक्ति जानता है और अपनी ऊर्जा किसी सार्थक चीज पर खर्च करता है।... अपने पतन में भी वह महान है, क्योंकि उसने साहस के साथ अपना जीवन जिया और वह उन बौनी सोच वाले लोगों से हमेशा ऊंचा ही रहेगा, जो कभी जीत या हार नहीं जान पाएंगे।

पाउलो कोएल्हो

आशुतोष राणा | अभिनेता

बच्चे राष्ट्र की आत्मा होते हैं, क्योंकि यही हैं, जिनके मस्तिष्क में अतीत सोया हुआ है; यही हैं, जिनके पहलुओं में वर्तमान करवटें ले रहा है और यही हैं, जिनके कदमों के नीचे भविष्य के अदृश्य बीज बोए जाते हैं।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले

खबरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जेड मोड़ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करने जम्मू-कश्मीर आए, तो राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिर से उनके सामने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग रखी। वाकई, यह इस राज्य की जरूरत है। जिस तरह से यह केंद्रशासित प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि इसे अब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। वैसे भी, यह वायदा केंद्र की तरफ से किया ही गया था कि उचित समय पर उसे अपना हक मिल जाएगा, तो मेरा मानना है कि यही उचित वक्त है, क्योंकि केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकार आम लोगों के हित में कई काम कर रही है। जब इस तरह के काम होते हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं खुद-ब-खुद बढ़ने लगती हैं। चूंकि बतौर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई तरह के फैसले इसलिए नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। लोगों और प्रदेश की भलाई के लिए केंद्र सरकार को इस मांग पर पुनर्विचार करना चाहिए।

धर्मेंद्र, टिप्पणकार

कुछ जरूरी सुझाव

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर विचार करते समय कई बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह सही है कि यहां शांति-व्यवस्था कुछ कायम हुई है और कहा जाने लगा है कि लाल चौक पर अब घूमने में कोई डर नहीं लगता, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी वहां आतंकी गतिविधियां जारी हैं। इसी के आधार पर एक तबका कह रहा है कि अगले कुछ वर्षों तक इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए व अभी इंतजार करना चाहिए। मगर हमें समझना चाहिए कि कुछ मांगों पर समय रहते गौर करना अनिवार्य होता है। अगर इसे अपना अधिकार मिल जाता है, तो जम्मू-कश्मीर और केंद्र का सहयोगात्मक रूप राज्य के विकास में काफी सहायक होगा। हालांकि, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि राज्य की शांति और स्थिरता में कोई सेंध न लगाने पाए। इसके साथ-साथ हमारे नीति-नियंताओं को उस पृष्ठभूमि पर भी गौर करना चाहिए, जिसके आधार पर इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। सन् 1947 की आजादी के बाद से ही इसने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का खामियाजा भुगता है। लिहाजा, अब वक्त है कि हम इसे इसका हक दें। हमें ऐसा निर्णय लेना ही होगा, जो इस राज्य और यहां के लोगों के विकास में सहायक साबित हो।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

पूर्ण राज्य

इसमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए

यह सही है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वायदा किया गया है, लेकिन ऐसा उचित वक्त पर ही होना चाहिए और यह उचित वक्त संभवतः अभी नहीं आया है। हमें देखना होगा कि पहले किस कदर राजनीतिक दल अलगाववाद के लिए ढाल की तरह काम करते थे, लेकिन अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद स्थिति बदल गई है और यही दल आतंकवाद के खात्मे की आवाज बुलंद करने लगे हैं। इसी तरह, विधानसभा सत्र की शुरुआत भी अलगाववादियों की कथित तारीफ के बजाय केंद्र द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना के साथ होती है। यह संकेत है कि जब से इससे विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया है, यहां की स्थिति में निरंतर सुधार आ रहा है, जिसका फायदा यहां के लोगों को ही नहीं, सैलानियों और अर्थव्यवस्था को भी हो रहा है।

असल में, इसे अभी पूर्ण राज्य का दर्जा देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त-बेवक्त पर यहां आतंकी घटनाएं हो ही रही हैं। सरकारें इनको रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन इक्का-दुक्का होने वाली घटनाएं बता रही हैं कि यहां की स्थिति अभी और सुधारने की जरूरत है। घुसपैठियों पर भी पूरी तरह से नकेल नहीं कस पाने से अलगाववादियों की आवाजें कभी-कभार सुनाई देने लगती हैं। इन सबको जब तक नियंत्रित नहीं कर लिया जाता, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से बचना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां भी इसी की पक्षधर हैं। खबरें बताती हैं कि वे भी इसे अभी पूर्ण राज्य का दर्जा देना उचित नहीं मानतीं, क्योंकि ऐसा करने से पुलिस-प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ सकती है और आतंकवाद निरोधी कार्रवाइयां प्रभावित हो सकती हैं। चूंकि यहां पर मौजूद आतंकियों के ईको-सिस्टम को खत्म करना आवश्यक है, इसलिए पहले इसे खत्म किया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, निहितार्थ यही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को फिलहाल अपने प्रदेश के विकास पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। केंद्र के साथ सहयोग बनाने में वह सफल रहे हैं। इसका लाभ उन्हें आगे भी उठाना चाहिए और केंद्र की मदद से ऐसी तमाम परियोजनाएं पूरी करनी चाहिए, जो यहां के लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी लाने का काम कर सके। ऐसा नहीं है कि मैं पूर्ण राज्य के दर्जा संबंधी विचार को ठंडे बस्ते में डालने के लिए कह रहा, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि उचित वक्त में इस प्रदेश को अपना हक दे दिया जाएगा, तो हमें प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा रखना चाहिए और उचित वक्त का इंतजार करना चाहिए।

विनीत कश्यप, टिप्पणीकार

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

झूठ न केवल अपने आप में बुरा है, बल्कि यह आत्मा को भी संक्रमित कर देता है। -सुकरात

बदलते वैश्विक परिदृश्य में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक महत्व जिस तरह से बढ़ा है, और चीनी आक्रामकता ने भी आशंकाएं बढ़ाई हैं, उसमें आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वाघशीर का नौसेना में शामिल होना देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम होने के साथ भारत की बढ़ती ताकत को भी रेखांकित करता है।

बढ़ती ताकत

देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित किया जाना भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने के साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का भी प्रतीक है। दरअसल, तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक व आर्थिक महत्व जिस तरह से बढ़ा है, और चीन के नौसैनिक बेड़े के लगातार विस्तार ने क्षेत्र के अस्थिर होने की आशंकाएं भी बढ़ाई हैं, उसमें आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वाघशीर का नौसेना में शामिल होना देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम होने के साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को भी रेखांकित करता है। उल्लेखनीय है कि इनमें से आईएनएस सूरत विश्व के सबसे बड़े और विध्वंसक जहाजों में से है, जो देश के समुद्री क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे को नष्ट करने की क्षमता रखता है। जबकि, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर क्रमशः अत्याधुनिक फ्रिगेट और पनडुब्बी हैं, जो लंबे समय तक समुद्र में रहने व शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने और समुद्र के भीतर छिपे खतरों से निपटने के लिए तैयार की गई हैं। वाघशीर की एक उल्लेखनीय खासियत है कि यह दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बी मानी गई है। दरअसल, इन तीनों का निर्माण कार्बन उत्सर्जन के वैश्विक पैमानों और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और इसका भी ख्याल रखा गया है कि समुद्र के भीतर पनडुब्बी आवाज न करे, जिससे यकीनन पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, तीनों का निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा किया जाना भी देश के लिए गौरवपूर्ण है, जिससे यह पता चलता है कि भारतीय नौसेना अब तकनीकी रूप से तो मजबूत हो ही रही है, यह भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश भी जाता है कि भारत अपनी सीमाओं और समुद्री हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। यही नहीं, आईएनएस सूरत व नीलगिरी, दोनों में महिला अधिकारियों व नाविकों को समायोजित करने की व्यवस्था है, जो निस्संदेह सैन्य भूमिकाओं में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक प्रगतिशील बदलाव को ही दर्शाती है। जाहिर है कि आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वाघशीर देश के समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति और सेनाओं के भीतर आधुनिकतम तकनीक और समावेशिता को अपनाने की प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं, जो देश की नौसैनिक क्षमताओं को फिर से परिभाषित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।

झूठ की ईंट पर आख्यान खड़ा करने की कला

एक धारणा गढ़ने के लिए जो अस्तित्व में न हो, उसे कल्पित से वास्तविक बनाने के लिए झूठे किस्से गढ़े जाते हैं। फिर, उसे सच की तरह दिखने वाली चमकदार पॉलिश की जाती है, ताकि सामान्य आदमी उसे स्थापित सत्य मान ले।

बलबीर पुंज
भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

अब सामने आया है कि जिस 'फातिमा शेख' को भारत की 'पहली मुस्लिम अध्यापिका' कहा जाता रहा है, उस शख्सियत का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। सार्वजनिक संवाद में इस तरह के धोखे अपवाद नहीं हैं। ये विश्वव्यापी 'टूलकिट' का हिस्सा हैं, जो काल्पनिक तथ्यों के आधार पर एक सुनिश्चित नैरेटिव के मायाजाल की रचना करते हैं। पिछली दो शताब्दियों में अर्धसत्य, सफेद झूठ और विकृत तथ्यों पर नैरेटिव गढ़ने की एक विशेष विधा विकसित हुई है, जिसका भारत भी शिकार है।

गत दिनों दलित-चिंतक दिलीप मंडल पर सोशल मीडिया में दावा किया कि उन्होंने बिना किसी ऐतिहासिक या पाठ्य-साक्ष्य के 'फातिमा शेख' नामक काल्पनिक चरित्र को गढ़ा था। मंडल का कहना है कि समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले (1827-90) और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले (1831-1901) की रचनाओं में कहीं भी 'फातिमा शेख' जैसा कोई नाम नहीं है, जो शिक्षिका रही हो। बकौल मंडल, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने भी फातिमा का उल्लेख नहीं किया था। अब मंडल ने ऐसा क्यों किया था, यह उन्होंने नहीं बताया। परंतु यह छल संभवतः उस 'दलित-मुस्लिम एकता' नामक नैरेटिव को तार्किक मजबूती देने का प्रयास था।

इस ताजा फर्जीवाड़े के उद्घाटित होने पर मुझे ऐसे कई मामले याद आते हैं, जिन्हें खास विचार के टूलकिट और निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु गढ़ा गया था। हैदराबाद विश्वविद्यालय के 26 वर्षीय पीएचडी छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी, 2016 को छात्रावास के अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब इस मामले को 'दलित हत्या' का विषय बनाकर भाजपा, आरएसएस और एबीवीपी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। यह स्थिति तब थी, जब रोहित अनुसूचित-जाति वर्ग (दलित) से नहीं था। अपनी मौत की सच्चाई को रोहित ने जिस सुसाइड नोट में लिखा था, उसे दबाने का भरसक प्रयास हुआ था। उस चिट्ठी में एक अनुच्छेद लिखकर काटा गया था, जिसमें रोहित ने अपने वामपंथी संगठन से मोहभंग होने की बात कही थी।

इसी तरह 23 सितंबर, 1998 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में चार ननों से सामूहिक बलात्कार को 'सांप्रदायिक' बना दिया गया था, जबकि यह दो समूहों के बीच आपसी विवाद से जुड़ा मामला था। तब प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बिना किसी साक्ष्य के इसका आरोप हिंदूवादी संगठनों पर मढ़ दिया। जांच के पश्चात इस अपराध में अदालत द्वारा दोषी वे स्थानीय आदिवासी पाए गए, जिन्हें इंजीलवादी-वामपंथी समूह हिंदू तक नहीं मानते।

गुजरात में गोधरा रेलवे स्टेशन के निकट 27 फरवरी, 2002 को जिहादियों ने ट्रेन के एक डिब्बे में 59 कारसेवकों को जिंदा जला दिया था। वर्ष 2004-05 में रेल मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने एक जांच समिति का गठन करके यह स्थापित करने का प्रयास किया कि गोधरा कांड मजहबी घृणा से प्रेरित न होकर केवल हादसा मात्र था। समिति की इस रिपोर्ट को गुजरात उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, तो कालांतर में अदालत ने मामले में हाजी बिल्ला, रज्जाक कुरकुर सहित 31 लोगों को दोषी ठहराया।

इस पूरे प्रकरण पर मुझे वामपंथी 'लेखिका' अरुंधति रॉय का दो दशक पुराना वह आलेख स्मरण होता है, जिसे उन्होंने एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी पत्रिका को लिखते हुए झूठा दावा किया कि दंगे में तत्कालीन कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की बेटी को निर्वस्त्र कर जिंदा जला दिया गया था। इस पर जाफरी के बेटे तनवीर ने खुलासा किया था कि तब उनकी बहन अमेरिका में थी। इस झूठ के लिए अरुंधति को माफी मांगनी पड़ी थी।

'भगवा आतंकवाद' सिद्धांत भी झूठ आधारित टूलकिट का ही एक सह-उत्पाद था। इस मिथक को कांग्रेस नीत संप्रगकाल (2004-14) में उछाला गया, जिसकी जड़ें 1993 के मुंबई शृंखलाबद्ध (12) बम धमाकों में मिलती हैं, जिनमें 257 मासूम मारे गए थे। तब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने आतंकियों की मजहबी पहचान और उद्देश्य से ध्यान भटकाने हेतु एक झूठ गढ़ दिया कि एक '13वां' धमाका मस्जिद के पास भी हुआ था। अपने इस सफेद झूठ पर पवार कई बार गौरवान्वित हो चुके हैं। यह सब प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से घटनाओं में 'हिंदू आतंकवाद' जोड़ने का प्रयास था, जिसे संप्रगकाल में पी. चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे सहित शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व ने आगे बढ़ाया। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने तो सभी सीमाओं को पार कर दिया था।

वर्ष 2008 में मुंबई पर भयावह 26/11 आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 29 विदेशी नागरिकों सहित 166 निरपराध मारे गए थे। आतंकवादी कसाब और डेविड हेडली (दाऊद सैयद गिलानी) के जीवित पकड़े जाने के बाद स्पष्ट हो गया था कि इस आतंकी हमले को पाकिस्तान में जिहादी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा', पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मिलकर रचा था। परंतु दिसंबर, 2010 में दिग्विजय सिंह ने '26/11-आरएसएस की साजिश' नामक मनगढ़ंत पुस्तक का लोकार्पण करके विमर्श ही उलटने की कोशिश की थी। यदि इसके कारणों को तलाशा जाए, तो यह केवल मुस्लिम वोटबैंक को रिझाने या पाकिस्तान को क्लीनचिट देने के प्रयास तक सीमित नहीं था वास्तव में, इसका मकसद इस्लामी आतंकवाद को 'न्यायोचित' ठहराने हेतु 'हिंदू आतंकवाद' का सिद्धांत गढ़ देना था।

बाटला हाउस सहित इस प्रकार के ढेरों उदाहरण हैं, जिन्हें उनके निहित एजेंडे के साथ लंबे समय तक चलाया जाता रहा है। तात्कालिक तौर पर बारंबार दोहराकर ये भ्रम विचार बना दिए जाते हैं और अंत में सत्य की तरह उद्धृत किए जाने लगते हैं। वर्तमान दौर में विषाक्त टूलकिट, युद्ध में उपयोग होने वाले किसी घातक हथियार की तरह है। एआई तकनीक के युग में यह और भी खतरनाक हो चुका है, जो केवल समाज को भ्रमित ही नहीं करता है, अपितु निरपराधों के खिलाफ हिंसा या वैमनस्य को भी बढ़ावा देता है। 'फातिमा शेख' पर हालिया खुलासे ने न सिर्फ उसी विषैले नैरेटिव के उद्देश्य की कलई खोली है, बल्कि ऐसे नैरेटिव की मारक क्षमता को पुनः रेखांकित किया है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

आचार्य रजनीश

ये जो करोड़ लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक अभीप्सा और एक प्रार्थना से, एक ध्वनि, एक धुन करते हुए आ गए हैं, यह एक संग्रह बन गया चेतना का। यह सामूहिकता की चेतना है। यहां अब व्यक्ति नहीं है।

कुंभ में ईश्वर का आह्वान करतीं चेतनाएं

इसमें कई बातें हैं। पहली बात जो समझ लेने की है, वह यह कि अगर कुंभ में देखें, तो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। भीड़, निपट भीड़, जहां कोई चेहरा नहीं है। चेहरा बचेगा कहां इतनी भीड़ में? निपट भीड़ रह गई, फेसलेस। एक करोड़ आदमी इकट्ठा हैं। कौन राजा है, कौन रंक है, अब कोई मतलब नहीं रह गया। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई मतलब नहीं रह गया, फेसलेस हो गया सब। और ये एक करोड़ आदमी एक ही अभीप्सा से एक विशेष घड़ी में इकट्ठे हुए हैं, एक ही प्रार्थना से, एक ही आकांक्षा से। इन सबकी चेतनाएं एक-दूसरे के भीतर प्रवाहित होनी शुरू होंगी। अगर एक करोड़ लोगों की चेतना का पूल बन सके, एक इकट्ठा रूप बन जाए, तो इस चेतना के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है, उतना आसान एक-एक व्यक्ति के भीतर नहीं है। यह बड़ा कांटैक्ट फील्ड है।

आदमी की चेतना कितना बड़ा कांटैक्ट फील्ड निर्मित करती है, परमात्मा का अवतरण उतना आसान हो जाता है। क्योंकि वह इतनी बड़ी घटना है! उस बड़ी घटना के लिए, जितनी जगह हम बना सकें, उतनी उपयोगी है। इंडिविजुअल प्रेयर (व्यक्तिगत प्रार्थना) तो बहुत बाद में पैदा हुई। प्रार्थना का मूल रूप, तो समूहगत है। वैयक्तिक प्रार्थना तो तब पैदा हुई, जब एक-एक आदमी को भारी अहंकार पकड़ना शुरू हो गया। और किसी के साथ पूल-अप होना मुश्किल हो गया कि किसी के साथ हम एक हो जाएं। और इसलिए जब से इंडिविजुअल प्रेयर दुनिया में शुरू हुई, तब से प्रेयर का फायदा खो गया। असल में प्रेयर इंडिविजुअल नहीं हो सकती। हम इतनी बड़ी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं कि हम जितना बड़ा क्षेत्र दे सकें, उसके अवतरण के लिए, उतना ही सुगम होगा।

तो तीर्थ उस बड़े क्षेत्र को निर्मित करते हैं। फिर खास घड़ी में करते हैं, खास नक्षत्र में करते हैं, खास दिन पर करते हैं, खास वर्ष में करते हैं। वे सब सुनिश्चित विधियां थीं। इसे भी समझ लेना चाहिए। जीवन की सारी व्यवस्था पीरियाडिकल है। जैसे कि वर्षा आती है, एक खास दिन पर आ जाती है। और अगर आज नहीं आती खास दिन पर, तो उसका कारण यह है कि हमने छेड़छाड़ की है। अन्यथा दिन बिल्कुल तय थे, घड़ी तय थी, सब तय था, वह उस वक्त आ जाती थी। गर्मी आती थी खास वक्त, सर्दी आती थी खास वक्त, वसंत आता था खास वक्त-सब बंधा था। शरीर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। स्त्रियों का मासिक धर्म है, वह ठीक चांद के साथ चलता रहता है। ठीक अट्ठाइस दिन में उसे लौट आना चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तो वह अट्ठाइस दिन में लौट आएगा। वह चांद के साथ यात्रा कर रहा है। वह अट्ठाइस दिन में नहीं लौटता, तो क्रम टूट गया है व्यक्तित्व का, भीतर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। सारी घटनाएं एक क्रम में आवर्तित होती हैं। तो अगर किसी एक घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया, तो उस घड़ी को हम अगले वर्ष के लिए फिर नोट कर सकते हैं। और संभावना उस घड़ी की बढ़ गई, वह घड़ी जो है वह ज्यादा पोटेंशियल हो गई, उस घड़ी में परमात्मा की धारा पुनः प्रवाहित हो सकती है। इसलिए पुनः-पुनः उस घड़ी में तीर्थ पर लोग इकट्ठे होते रहेंगे, सैकड़ों वर्षों तक।

-('गहरे पानी पैठ' के संपादित अंश)
-स्वामी चैतन्य कीर्ति।

दूसरा पहलू

सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर आठ दिन के लिए अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, लेकिन उनको सात महीने हो चुके हैं।

अंतरिक्ष में अकेलेपन को झेलना इतना भी आसान नहीं

अगर कोई अंतरिक्ष यात्री आठ दिन के अंतरिक्ष अभियान पर गया हो। किन्हीं वजहों से वह सात महीनों तक धरती पर न लौट सके, तो सामान्य व्यक्तियों के लिए इसकी कल्पना ही रोंगटे खड़े करने वाली होगी। लेकिन भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स व उनके साथी बुच विलमोर की बात ही अलग है। नासा के ये दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून, 2024 को आठ दिन के अभियान पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी की वजह से वे पिछले सात महीनों से अंतरिक्ष में ही अटके हुए हैं। पिछले साल सितंबर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान विलमोर ने कहा था कि वह अपनी छोटी बेटी की हाईस्कूल की परीक्षाओं की तैयारी को याद कर रहे हैं।

ईडो मिजराही

पिछले साल सितंबर में विलमोर ने कहा था कि वह अपनी छोटी बेटी की हाईस्कूल की परीक्षाओं की तैयारी को याद कर रहे हैं।

1986 में तत्कालीन सोवियत संघ ने अपने पहले मॉड्यूलर लो अर्थ ऑर्बिट अंतरिक्ष स्टेशन मीर का प्रक्षेपण किया, जिसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना भी शुरू किया। लेकिन 1995 में मीर में रह रहे एक अंतरिक्ष यात्री ने अपनी मानसिक स्थिति को लेकर चेतावनी दी थी कि अगर उसका मिशन छह महीने और बढ़ा दिया गया, तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। यही वह समय था, जब नासा बेहद शांत ढंग से मनोवैज्ञानिकों की एक यूनिट तैयार कर रहा था, जो लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान यात्रियों को मानसिक तौर पर शांत रख सके। 2011 के करीब एक बार एक अंतरिक्ष यात्री की मां गुजर गईं, एक अन्य अभियान में अंतरिक्ष यात्री की भाभी की हत्या हो गई, तो जब सुनामी ने जापान को तबाह किया, तो ये दृश्य भी चालक दल के सदस्यों ने देखे। मनोवैज्ञानिक यूनिट ने इन तनावपूर्ण क्षणों को संभालने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का भरोसा जीतना शुरू किया। यूनिट ने एक अंतरिक्ष यात्री को वह फिल्म भेजी, जिसमें वह बच्चे को जन्म दे चुकी थी, इसी तरह एक अंतरिक्ष यात्री और धरती पर मौजूद उसकी मंगेतर का विवाह भी संपन्न कराया। लेकिन मंगल मिशन की बात अलग होगी, जहां तक आने और जाने में ही तीन साल लगेंगे। इस दौरान संचार पूरी तरह से टूट भी सकता है। ऐसे में अब अंतरिक्ष यात्री भी वैसे चुने जा रहे हैं, जो लंबे समय तक अलगाव के मानसिक तनाव को झेल सकें। सुनीता विलियम्स व विलमोर जैसे अंतरिक्ष यात्री भी तेजी से स्थितियों से तालमेल बैठाना सीख रहे हैं। जैसा सुनीता विलियम्स एक वीडियो में कहती भी दिख रही हैं, 'यही वह जगह है, जहां मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है।'

1995 में मीर में रह रहे अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि यदि मिशन बढ़ाया गया, तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। इसी दौरान नासा ने मनोवैज्ञानिकों की एक यूनिट तैयार की, जो लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान यात्रियों को तैयार कर सके।

©The New York Times 2025

आंकड़े

खुदरा महंगाई

दिसंबर 2024 में देश की खुदरा महंगाई 5.22 फीसदी रही। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं, जिनमें खुदरा महंगाई दर काफी अधिक है।

छत्तीसगढ़	7.63%
बिहार	7.36%
ओडिशा	6.96%
केरल	6.36%
उत्तर प्रदेश	6.26%

आंकड़े दिसंबर 2024 में ज्यादा महंगाई वाले राज्यों के, प्रतिशत में | स्रोत : MoSPI

बादशाह के लिए बनाए तकिये भक्त परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दिए। परमेष्ठी जी को जेल में डाल दिया गया, पर ईश्वर की लीला से बादशाह घबरा गया।

बादशाह ने परमेष्ठी से मांगी माफी

अंतर्यात्रा
संकलित

लगभग चार सौ वर्ष पूर्व दिल्ली में परमेष्ठी नाम के दर्जी रहते थे। उनके हृदय में भगवान वासुदेव की भक्ति भरी हुई थी और हाथों में कारीगरी। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे दो बढ़िया गलीचे बिछाए गए। बादशाह को गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने दो तकिये बनवाने का विचार किया।

बादशाह ने परमेष्ठी को बुलवाकर दो सुंदर तकिये तैयार करने के लिए कहा। तकिये तैयार हुए। जेवरात लगे होने से तकिये चमक उठे थे। भक्त परमेष्ठी ने सोचा, 'कितने सुंदर हैं ये तकिये?' इनके अधिकारी, तो भगवान जगन्नाथ जी हैं। उस दिन जगन्नाथ जी की रथयात्रा थी। उन्होंने ध्यान करते हुए, भगवान से एक तकिये को स्वीकारने की प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, और देखा उनके पास एक ही तकिया है। परमेष्ठी जी को बड़ा आनंद हुआ। प्रभु ने एक तकिया स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी जी बादशाह से बोले, 'एक तकिया जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया।' बादशाह ने दूसरा तकिया नहीं होने की वजह से परमेष्ठी जी को कारागार में डलवा दिया। जेल में भी वह भगवान मधुसूदन का ही ध्यान करते रहे। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने बादशाह को स्वप्न में ताड़ना दी। घबराए हुए बादशाह ने स्वप्न की बात अपने विश्वास पात्रों को बताई और जाकर देखा कि कारागार खुला पड़ा है। इसके बाद बादशाह ने भक्त परमेष्ठी से माफी मांगी और उन्हें रिहा किया।

अमर उजाला पुराने पन्नों से — 03 सितंबर, 1963

भारत की विदेश नीति सही सिद्ध हुई : नेहरू

भारत की विदेशनीति सही सिद्ध हुई है : श्री नेहरू

प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्यसभा में कहा कि यह कहना कठिन है कि चीन निकट भविष्य में भारत पर हमला करेगा, लेकिन हम पूरी शक्ति के साथ तैयार हैं। उन्होंने कहा, भारत की विदेश नीति सही सिद्ध हुई है।

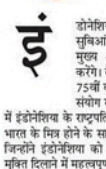

75 साल बाद गणतंत्र दिवस पर फिर इंडोनेशिया

भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, जो द्विपक्षीय संबंधों में सततता को उजागर करता है।

विवेक शुक्ला | विदेश नीति

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। देश इस बार गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। संयोग से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। वह भारत के मित्र होने के साथ-साथ एक करिश्माई नेता थे, जिन्होंने इंडोनेशिया को डच औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने उन्हें बहुत सोच-विचार करने के बाद देश के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया था। उनके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उड़ीसा (अब ओडिशा) के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक और कई अन्य नेताओं से गहरे संबंध थे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह भारत की विदेश नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। देखा जाए, तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना, भारत और उस देश के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक अवसर भी है।

गणतंत्र दिवस एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहां भारत अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ सकता है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रख सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने का एक मंच है। एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति इस अवसर को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है और दुनिया भर में भारत की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देती है। यह निमंत्रण सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा अवसर होता है, जब आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष भारतीय संस्कृति, परंपराओं और उपलब्धियों को करीब से देख पाते हैं। एक बात और कि कभी-कभी यह एक राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष देश को आमंत्रित करना, उस देश के प्रति भारत के समर्थन या प्रशंसा का संकेत हो सकता है।

भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह राजधानी के नेशनल स्टेडियम (अब ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम) में आयोजित किया गया था। पहले और 75 साल बाद फिर गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे संबंधों का एक स्पष्ट प्रमाण है। गणतंत्र दिवस पर वार्षिक अतिथियों के क्रम में पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। वह जब कर्तव्य पथ पर पधारे होंगे, तो उन्हें इंडिया गेट को देखकर अच्छा लगा होगा। कारण यह है कि इंडिया गेट और पेरिस में स्थित द आर्क डी ट्रायंफ में गजब की समानता है। इंडिया गेट बना था प्रथम विश्वयुद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में। वहां पर शहीदों के नाम भी अंकित हैं। द आर्क डी ट्रायंफ उन शहीदों की याद में बनाया गया था, जो फ्रांस के लिए विभिन्न जंगों में लड़े और अपनी जान दी। लगता है कि एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन बनाते हुए फ्रांस के सबसे बड़े प्रतीक द आर्क डी ट्रायंफ को गहराई से देखा होगा।

यों तो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुख्य अतिथि रहे हैं, पर दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति योद्धा नेल्सन मंडेला और महान मुक्केबाज मोहम्मद अली का कर्तव्य पथ पर सबसे गर्मजोशी से उपस्थित अपार जनसमूह ने स्वागत किया था। मंडेला 1995 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। मंडेला जब परेड का आनंद ले रहे थे, तब वहां मौजूद दर्शक मंडेला के नारे लगा रहे थे।

गणतंत्र दिवस परेड का लंबे समय तक आंखों देखा हाल सुनाने वाले जसदेव सिंह बताते थे कि मंडेला की तरह कर्तव्य पथ पर उपस्थित अपार जनसमूह ने मुक्केबाज मोहम्मद अली का भी करतल ध्वनि से अभिनंदन किया था। वह 1978 के गणतंत्र दिवस समारोह में खास अतिथि थे। उस गणतंत्र दिवस समारोह में कहने को मुख्य अतिथि आयरलैंड के राष्ट्रपति पेट्रिक हिलेरी थे, पर सबकी निगाहें मोहम्मद अली को तलाश रही थीं। वह अपने चाहने वालों के अभिवादन का उत्तर अपने मुक्के को हवा में घुमाकर दे रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मोहम्मद अली को देखकर मुस्करा रही थीं। बहरहाल, भारत आगे भी मित्र देशों के नेताओं को गणतंत्र दिवस समारोहों में आमंत्रित करता रहेगा।

कल्पमेधा

जो शासन करते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। आखिरकार जनता ही मुखिया होती है।
- लाल बहादुर शास्त्री

संदेह की सरहद

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव लंबे समय से है, मगर करीब पांच वर्ष पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक परस्पर गुत्थमगुत्था हो गए, तबसे तल्खी कुछ अधिक बनी रही है। हालांकि बीते अक्तूबर में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि वे पूर्वी लद्दाख से अपनी सेनाएं वापस बुलाएंगे और एक-दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास नहीं करेंगे। उसके बाद रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों देशों के प्रमुखों ने फिर से हाथ मिलाया और रणनीतिक मुद्दों पर अलग से बातचीत की। इससे दुनिया को यही संदेश गया कि भारत और चीन के रिश्तों में आई कड़वाहट अब दूर हो गई है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव की स्थितियां फिर नहीं बनेंगी। मगर सेना दिवस से दो दिन पहले और फिर सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना प्रमुख ने जिस तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा की हकीकत बयान की, उससे यही जाहिर हुआ है कि भारत अब भी चीन को लेकर सतर्क है। सेना प्रमुख ने कहा कि वहां स्थिति अभी संवेदनशील है और कुछ मसलों पर गतिरोध बरकरार है, जिस पर बैठ कर व्यापक समझ बनाने की जरूरत है।

दरअसल, चीन का कोई भी कदम संदेह से परे नहीं होता। उसने जिस तरह लद्दाख से सेनाओं की वापसी पर सहमति जताई और फिर उस इलाके में निर्माण कार्य शुरू किए, उससे जाहिर है कि वह अपनी रणनीति पर पीछे हटने को तैयार नहीं। टकराव से बचने के लिए अब भी उस क्षेत्र में सैनिकों की गश्त पर अस्थायी रोक है। अब इस बात के भी पुख्ता प्रमाण हैं कि 2020 में हुए सैन्य टकराव के बाद चीन ने भारतीय अधिकार वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया और कुछ जगहों पर गांव और प्रशासनिक इकाइयां बसा दी। वहां उसने बड़ी मात्रा में आयुध सामग्री जमा कर रखी है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने अतिरिक्त सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला करना कठिन बना हुआ है। चीन ऐसी चालें चलता रहता है कि वह जिन मुद्दों पर समझौता करता है, उन्हीं के विरुद्ध कदम भी उठाता रहता है। ऐसे में भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। सेना प्रमुख ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें विश्वास बहाली को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है।

यह अच्छी बात है कि सेना प्रमुख ने वास्तविकता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार और बड़ी साफगोई से अपनी रणनीति का इजहार किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा की हकीकत पर प्रायः पर्दा डालते देखा जाता रहा है, मगर सेना प्रमुख ने ऐसा नहीं किया। मगर वहां जिन क्षेत्रों में स्थिति संवेदनशील बताई और चीन के अतिक्रमण को रेखांकित किया जा रहा है, उसमें केवल दोनों तरफ की सेनाओं के अधिकारियों के बीच बैठकों और बातचीत के सिलसिले से कोई स्थायी समाधान की उम्मीद शायद ही बने। इसके लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास करने होंगे, जो कि अभी तक अवरुद्ध ही नजर आ रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों में वैसी गर्मी नहीं लौट पाई है, जिसके आधार पर कहा जा सके कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा। इसके लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने होंगे। अच्छी बात है कि इसे लेकर भारतीय सेना सतर्क है, पर संजीदा राजनीतिक प्रयासों से उसे और ताकत मिलेगी।

महंगाई का बोझ

थोक महंगाई दर ने एक बार फिर झटका दिया है। महंगाई पर काबू पाना पहले से कठिन बना हुआ है। थोक महंगाई के ताजा आंकड़े ने आर्थिक प्रबंधकों की बेचैनी बढ़ा दी है। इससे उत्पादकों पर दबाव बढ़ा है। यह कम चिंता की बात नहीं है कि तमाम प्रयासों के बावजूद डालर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। वहीं उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति पहले से कहीं अधिक कम हो गई है। लिहाजा, बाजारों में वैसी रौनक नहीं, जैसी अपेक्षा व्यवसायी करते रहे हैं। ऐसे में महंगाई दर का बढ़ना अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों से पता चलता है कि महंगाई दबे पांव बढ़ती चली गई है। खाने-पीने की चीजों के दामों में थोड़ी-बहुत नरमी बीच-बीच में जरूर दिखती रही, लेकिन ईंधन, विनिर्मित उत्पाद और गैर-खाद्य वस्तुओं के मूल्य जिस तरह बढ़े हैं, उसे थामा नहीं जा सका। काफी समय से उत्पादन क्षेत्र की रफ्तार सुस्त बने रहने का असर है कि थोक महंगाई बढ़ी है। थोक भाव अधिक समय तक ऊंचा बने रहने से उत्पादों की बढ़ी कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

खुदरा महंगाई में मामूली गिरावट से भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। हालांकि यह चार महीने के निचले स्तर पर है। बीते वर्ष नवंबर में यह 5.48 फीसद थी, जो दिसंबर में 5.22 फीसद पर आ गई। जबकि यही दर अगस्त में 3.65 फीसद थी। इस लिहाज से ताजा गिरावट को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इन सभी आंकड़ों के आधार पर मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरें कम करने की स्थिति में आएगी, इसमें संदेह है। बावजूद इसके, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि समिति की अगली बैठक में काफी दबाव रहेगा। आशंका है कि थोक महंगाई बढ़ने का असर कहीं खुदरा महंगाई पर न दिखाई दे। इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकार के ताजा आंकड़े से हर उपभोक्ता की चिंता बढ़ गई है, जो अभी बहुत मुश्किल से घर चला रहा है। फिलहाल महंगाई में स्थिरता की उम्मीद तो नहीं नजर आ रही, पर इसे सहनशील स्तर पर लाने का प्रयास होना चाहिए।

तरक्की के बरक्स पोषण की चुनौती

विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (सोफी) रपट 2023 में कहा गया है कि भारत में पोषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। भारत में 2020 और 2022 के बीच 7.4 करोड़ लोग अल्पपोषण का शिकार थे।

जयंतीलाल भंडारी

भारत में गरीबी और पोषण से संबंधित विभिन्न अध्ययन रपटों में यह तथ्य रेखांकित हो रहा है कि गरीबी में लगातार कमी आ रही है, लेकिन लोगों के भोजन में पोषक तत्त्वों की कमी चुनौती बनी हुई है। 'स्टेट बैंक आफ इंडिया रिसर्च' द्वारा गरीबी पर जारी रपट में कहा गया है कि गरीबों को सीधे लाभान्वित करने वाले सरकारी सहायता कार्यक्रमों के कारण गरीबी में कमी आई है। वहीं विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (सोफी) रपट 2023 में कहा गया है कि भारत में पोषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। वर्ष 2020 और 2022 के बीच 7.4 करोड़ लोग अल्पपोषण के शिकार थे। इस रपट का विश्लेषण दर्शाता है कि रोजाना दो बार भोजन की परिभाषा के अनुसार भारत में भूख की समस्या तुलनात्मक रूप से कम हुई है यानी आबादी के बड़े हिस्से की अनाज संबंधी जरूरतें मोटे तौर पर पूरी हो रही हैं। मगर पोषक आहार की कमी बनी हुई है। इसी प्रकार वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 125 देशों के बीच भारत को 111वां स्थान दिया गया है।

एसबीआइ रिसर्च की रपट में कहा गया है कि गरीबी में कमी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से हुई है। जहां वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7 फीसद और शहरी गरीबी 13.7 फीसद थी, वहीं वर्ष 2023-24 में ग्रामीण गरीबी घट कर 4.86 फीसद और शहरी गरीबी घट कर 4.09 फीसद पर आ गई। इस रपट के मुताबिक पिछले 14 वर्ष में आमदनी बढ़ने से, जहां शहरों में हर माह प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता खर्च (एमपीसीई) 3.5 गुना हो गया, वहीं यह ग्रामीण इलाकों में करीब चार गुना हो गया है। वर्ष 2009-10 से 2023-24 के बीच शहरी इलाकों में उपभोक्ता खर्च 1984 रुपए से बढ़ कर 6996 रुपए और ग्रामीण इलाकों में यह 1054 रुपए से बढ़ कर 4122 रुपए हो गया। ऐसे में शहरों की तुलना में गांवों में यह खर्च ज्यादा है।

गौरतलब है कि बीती चार जनवरी को प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में ग्रामीण गरीबी में तेजी से कमी आ रही है। यह पिछले वर्ष 2024 में घट कर पांच फीसद से भी कम रह गई है। साथ ही ग्रामीणों की आमदनी और क्रयशक्ति बढ़ी है। गांवों के लाखों घरों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। लोगों को डेढ़ लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। डिजिटल तकनीक की मदद से बेहतरीन डाक्टर और अस्पताल भी गांवों से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए देश को किसानों को तीन लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। बीते दस वर्षों में कृषि ऋण साढ़े तीन गुना बढ़ गए हैं। अब पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। बीते दस वर्षों में फसलों पर दी जाने वाली सबसिडी और फसल बीमे की राशि को बढ़ाया गया है। स्वामित्व योजना जैसे अभियान चलाए गए हैं, जिनके जरिए गांवों के लोगों को संपत्ति के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, 'स्टार्टअप इंडिया' और 'स्टैंड अप इंडिया' जैसी योजनाओं के जरिए मदद की जा रही है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने उनकी गरीबी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज दिया जाना सुनिश्चित किया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि देश में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को व्यवस्थित रूप से निशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की भूमिका प्रभावी बनाई गई है। देश भर में मौजूदा पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है। वर्ष 2016 से राशन की दुकानों में पाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनों की शुरुआत से रिसाव में कमी आई है।

> वैश्विक रपटों में भी भारत में गरीबों के सशक्तीकरण और विकास से गरीबी में कमी आने और उत्पादकता में वृद्धि होने के विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की दुनिया में गरीबी संबंधी रपट में कहा गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या वर्ष 1990 में 43.1 करोड़ थी। यह घटते हुए 2021 में 16.74 करोड़ रह गई और वर्ष 2024 में करीब 12.9 करोड़ ही रह गई है। नीति आयोग की तरफ से वैश्विक मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) 2024 के मुताबिक पिछले दस वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं।

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि डिजिटल इंडिया, स्वच्छ पेयजल और आयुष्मान भारत योजना और स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना अभियानों से देश में गरीबी में कमी आ रही है। खासतौर से करीब 54 करोड़ से अधिक जनधन खातों, करीब 138 करोड़ आधार कार्ड और करीब 115 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं की शक्ति से सुगठित बेमिसाल डिजिटल ढांचा गरीबों के सशक्तीकरण में असाधारण भूमिका निभा रहा है। इसके बल पर देश के गरीब लोगों के खातों में सीधे राहत राशि हस्तांतरित हो रही है। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी से लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा हो चुकी है। इन सबसे गरीबी में बड़ी कमी आई है और ग्रामीण भारत विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है।

वैश्विक रपटों में भी भारत में गरीबों के सशक्तीकरण और विकास से गरीबी में कमी आने और उत्पादकता में वृद्धि होने के विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की दुनिया में गरीबी संबंधी रपट में कहा गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या वर्ष 1990 में 43.1 करोड़ थी। यह घटते हुए 2021 में 16.74 करोड़ रह गई और वर्ष 2024 में करीब 12.9 करोड़ ही रह गई है। नीति आयोग की तरफ से वैश्विक मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) 2024 के मुताबिक पिछले दस वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। दुनिया के ख्यात अर्थशास्त्री थामस पिकेटी का कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ता विकास आम आदमी की आमदनी बढ़ा रहा है और गरीबी में तेजी से घटने की प्रवृत्ति उभर रही है।

लोक कल्याणकारी योजनाओं से गरीबी और भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायता मिली है, लेकिन अभी भी बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे करीब 15 करोड़ से अधिक गरीबों को सरकार के लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2030 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए और अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि यद्यपि गरीबों के सशक्तीकरण के साथ देश में प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी भारत दुनिया के उन प्रमुख दस देशों में शामिल है, जहां बीते बीस वर्षों में लोगों की आय में असमान इजाफा हुआ है। देश के करोड़ों गरीबों के लिए हमें ऐसी नीतियां चाहिए, जो उनके लिए पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन के वितरण, उपलब्धता तय करने और उसे किफायती रखने में मददगार हो सकें।

उम्मीद है कि सरकार वर्ष 2025 में देश से गरीबी और घटाने के लिए सशक्तीकरण की योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के साथ नई योजनाओं और नए रणनीतिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ेगी। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार देश में बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे करीब पंद्रह करोड़ से अधिक लोगों को 2030 तक गरीबी से बाहर लाने के लक्ष्य पर ध्यान देगी।

कड़वाहट का कलुष

दुनिया मेरे आगे

मयंक मुरारी

आज की दुनिया में अपने आसपास का व्यवहार देख कर यही लगता है कि इंसान बहका हुआ है। उसने हर जगह के लिए एक मुखौटा बना रखा है। भोलेपन के पीछे कड़वाहट का समंदर है, लेकिन वह अपनी कलुषित भावना से उसको छिपाना चाहता है। ऐसा करते हुए यह भूल जाते है कि हम एक भीड़ हैं। हमारे हजारों मुखौटे हैं। घर में अलग मुखौटा है। उसमें भी माता-पिता के सामने अलग मुखौटा, बच्चों के सामने अलग, पत्नी के सामने अलग, पेशेवर मित्रों के सामने अलग, लंगोटिया मित्रों के सामने अलग, मालिक के सामने अलग और नौकर के सामने अलग। हमारे कितने चेहरे हैं, शायद हमको खुद ही नहीं पता। समाज में जीने के लिए आज यह आवश्यक हो सकता है, लेकिन जीवन जीने में यह मुखौटा पूरी यात्रा के आनंद को कड़वाहट में बदल देता है।

जीवन में कड़वाहट का मुख्य कारण अपनी इच्छा और विचार को सर्वोपरि रखना है। इस कारण रिश्तों में दरार, बिखराव और टूटन आता है। आजकल अधिकतर लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता की बहुत कमी है। लोग छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। घर से बाहर की बात तो दूर, एक घर के अंदर रहने वाले एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को सम्मान नहीं देते और वाद-विवाद में पड़ जाते हैं। बचपन से जो पिलाया जाता है, वही बच्चे की नस-नस में बस जाता है। बच्चे घर से ही रिश्तों की अवहेलना सीख जाते हैं और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। रिश्तों को निभाने के लिए झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तब कहीं जाकर रिश्ते मधुर होते हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करना बंद कर देते हैं, तब रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। कई बार गलतफहमियां भी रिश्ते में कड़वाहट ले आती हैं। कभी-कभी अगर एक पक्ष गलत हो और दूसरा पक्ष सही होते हुए भी उसे बार-बार दबना पड़े तो भी रिश्ते कड़वे हो जाते हैं। कई बार जब हम छोटे और बड़े का यथायोग्य आदर या स्नेह देना बंद कर देते हैं या फिर फालतू का शक करने लगते हैं, तब भी रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है।

> जीवन में कड़वाहट का मुख्य कारण अपनी इच्छा और विचार को सर्वोपरि रखना है। इस कारण रिश्तों में दरार, बिखराव और टूटन आता है। आजकल अधिकतर लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता की बहुत कमी है। लोग छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं।

रिश्ते हमारी अमूल्य निधि होते हैं। अगर रिश्तों को बरकरार रखने के लिए हम थोड़ा झुकने के बाद भी रिश्तों को बचा लें, तो यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि होगी। मगर आज झुकना कोई नहीं चाहता है, न ही रुकना। इसलिए हर पड़ाव पर हम खुद का ही मोल लगा बैठते हैं। विनम्रता से हर कोई समझ ही जाता है, लेकिन अगर थोड़ा-बहुत मनमुटाव हो भी, तो भी रिश्ता खत्म नहीं किया जाना चाहिए। विडंबना यह है कि ज्यादातर रिश्ते आजकल दिखावटी रह गए हैं। सहनशीलता और एकता खत्म होती जा रही है। रिश्तों में विश्वास जरूरी है, जहां विश्वास होता है, वहीं प्यार पनपता है। बिना विश्वास प्यार की कल्पना नहीं की जा सकती।

हमारे पूर्वज हमें जीवन और रिश्तों के बारे में एक तरह का खाका या मानसिकता देकर जाते हैं। यह मानसिकता हमारे रिश्तों के खुशहाल होने का एक प्रमुख निर्धारण कारक है। स्थायी परिवर्तन तभी आएगा, जब हम इन वफादारियों के बारे में जागरूक होंगे। जीवन में अपने रिश्ते को ठीक करने के ज्ञान को एकीकृत करने से हमें खुद को ठीक करने की शक्ति और अंतर्दृष्टि मिलेगी और निश्चित रूप से हमारे रिश्ते के कौशल में सुधार होगा। इसके लिए जीवन में सच्चे विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास प्राप्त करने का पहला साधन है व्यक्तिगत अनुभव और उससे उभरता भरोसा। यह भरोसा किसी वस्तु या व्यक्ति में भी हो सकता है। विश्वास रूपी गुण को उजागर करने से शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की अनुभूति होती है। ये शक्तियां व्यक्ति को अनुशासित और धैर्यवान बनाती हैं। इन्हीं के बल पर वह इंसान ईश्वरत्व के समीप पहुंचता है। और साथ ही उसके प्रति चिंताएं कम होने लगती हैं और एक पारलौकिक आनंद का अनुभव ज्यादा होने लगता है।

संसार में हमारी जो भी यात्रा होती है- काम, धन, पद-प्रतिष्ठा की, उसके केंद्र में आनंद की खोज ही है। लेकिन अगर मार्ग गलत हो तो लक्ष्य कैसे मिल सकता है। उसी तरह ये सारी यात्राएं हालांकि जीवन आनंद की खोज के लिए है, पर यह दौड़ उल्टी दिशा में है। इसलिए आनंद के स्थान पर मिलते हैं असहजता, दुख, उदासी, बेचैनी। मन के निर्मल होने का, उसको निर्मल करने का कोई मार्ग नहीं है। निर्मलता मन के पार जाने की दशा है। शरीर मन और आत्मा- ये तीन परतें हैं हमारे अस्तित्व की। अन्न, जल, कपड़ा और मकान। बड़ी सीमित अवश्यताएं हैं शरीर की। अगर शरीर स्वस्थ हो तो उसकी हम न चिंता करते हैं, न उसे कोई महत्त्व देते हैं।

फिर आता है मन। विचारों और भावनाओं का डेटा संकलित करने वाला यंत्र। यही हमारे समस्त अवसादों, बेचैनियों, और उपद्रवों की जड़ है। मन में हमारे जो भी घटता है, हम उसी के अनुसार काम करते हैं। मन है विचारों की वह भीड़ जो हमने बचपन से आज तक बटोर रखा है। इसमें बहुत सारे विचार एक दूसरे के विरोधी हैं। हम कभी इस विचार के साथ बहते हैं, कभी उस विचार के साथ। इस तरह हम खंड-खंड में जीते हैं। यही विचारों की भीड़ हमें चलाती है, नियंत्रित करती है। जिसका स्वभाव ही मैला होना है, उसे निर्मल करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। विचारों से मुक्त मन ही निर्मल मन है, जहां रिश्तों की एक अनमोल यात्रा शुरू होती है। भोलापन नहीं, बल्कि बहुत धैर्य, समझ और आत्मिक ज्ञान के साथ अपने रिश्तों की समस्याओं के मूल कारणों तक जाना होता है। वफादारी से ज्यादा जरूरी है दूसरे को समझने की। इससे संबंध प्रगाढ़ होता है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चौपाल

रिश्तों में तल्खी

पिछले कुछ महीनों में हुए घटनाक्रम से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में काफी तल्खी आई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ। धार्मिक स्थलों पर हमले हुए। मगर इन घटनाक्रमों पर अंकुश लगाने के बजाय बांग्लादेश का रुख और ज्यादा उग्र हुआ है। यह काफी तकलीफदेह है। ऊपर से पाकिस्तान के साथ उसकी जुगलबंदी भी हैरान करने वाली है। बांग्लादेश के नेतृत्व और सेना अधिकारियों द्वारा उग्र बयानबाजी ने भारत को काफी तकलीफ पहुंचाई है। जिसकी वजह से उसका निर्माण हुआ, आज वही इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर भारत को धमका रहा है। भारत की आशंका निर्मूल नहीं है कि बांग्लादेश सीमा से पाक आतंकवादियों की घुसपैठ हो सकती है। इसीलिए सीमा पर बाड़बंदी का फैसला उचित ही है। सदाशयता दोनों तरफ से होती है, एकतरफा नहीं। भारत के साथ मित्रता के सान्निध्य में जो उसने कमाया वो सब गंवा सकता है। यदि बांग्लादेश को लगता है कि भारत के बजाय पाकिस्तान के साथ मित्रता में उसका हित ज्यादा है, तो यह उसका भ्रम है। यह उसकी नासमझी भी है। वह अतीत को भूल गया है। वर्तमान में वह आग से खेल रहा है।

- चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

भाषा और पहचान

हिंदी भारतीयों की पहचान है। हर व्यक्ति की अपनी भाषा दरअसल उसकी दुनिया होती है। ऐसी दुनिया जिसमें भूगोल है, तो इतिहास भी और संस्कृति के साथ परंपरा भी शामिल हैं। भारत में हिंदी भाषा की स्थिति महत्त्वपूर्ण और जटिल दोनों है। एक ओर हम हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने की ओर अग्रसर हैं, वहीं दूसरी ओर देश में हिंदी की स्थिति दयनीय होती जा रही है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर अंग्रेजी हावी हो रही है। भारत में पिता पिताश्री से पापा, अब डैडी बन चुके हैं, तो वहीं माताश्री मम्मी से होते हुए माम तक पहुंच चुकी है। देश की नई पीढ़ी बदल रही है। वह अपनी संस्कृति और परंपरा से लगातार दूर हो रही है। हिंदी भाषा के प्रति दूरदर्शी सोच रखने वाले राजनेताओं के कारण हिंदी वैश्विक स्तर पर सफलता का परचम फहराने की स्थिति में आगे बढ़ रही है। भारत सरकार हिंदी के प्रचार-प्रसार को लेकर बहुत सजग है। हिंदी हमारी संस्कृति और सभ्यता की सच्ची वाहक है।

- रतन सिंह, बरेली

पीढ़ी परिवर्तन

इंटरनेट पर सक्रिय पीढ़ी को सब कुछ मालूम होता है। उन्हें यह भी पता है कि जेनरेशन बीटा का आगाज हो गया है। अब नई पीढ़ी ऐसी होगी, जिनके जीवन का पल-पल तकनीक की बुनियाद पर संवरेगा। यह पीढ़ीगत बदलाव है। पहले के दौर में पीढ़ियों पर इतनी गहराई से काम नहीं होता था, लेकिन अब यह काम मुस्तैदी से हो रहा है। क्योंकि इसी में बाजार का अपना हित है। लोगों की मानसिकता को समझना बाजार के लिए जरूरी है। बाजार को भी यह चिंता है कि नई पीढ़ी किस तरह का व्यवहार करेगी, उसे किस दिशा में ले जाना ज्यादा मुफीद रहेगा। आस्ट्रेलियाई रुझान और जनसांख्यिकी विश्लेषण कंपनी मैककिंडल ही पीढ़ी का नामकरण करती है। इसी कंपनी ने दुनिया को बताया है कि जेनरेशन बीटा अर्थात जेन बीटा में वर्ष 2025 से 2039 के बीच पैदा हुए लोग शामिल रहेंगे। हर पंद्रह साल में पीढ़ी परिवर्तन होता है। सबसे खास बात यह है कि बीटा पीढ़ी के अनेक लोग अगली सदी के भी दर्शन करेंगे।

- अनुप्रिया रजक, टीकमगढ़

मुद्रा में गिरावट

संपादकीय 'छीजता खजाना' (तेरह जनवरी) में उल्लेख है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होगी, जिससे विदेशी निवेश में कमी होने का अंदेशा है। उपभोक्ता व्यय और क्रय शक्ति में कमी के मद्देनजर रिजर्व बैंक भी ब्याज दर में कटौती कर सकता है, अस्तु रुपए की गिरावट को हर हालत में रोकना होगा। दो वर्ष में सबसे ज्यादा रुपए की गिरावट होने से एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा में रुपया शामिल हो गया है। डालर के मुकाबले अब तक का सबसे बड़ा और निचला स्तर 86 से ऊपर चला गया है। रुपए की गिरावट से घाटे के व्यापार में इजाफा, निर्यात कम, आयात अधिक और परिवहन लागत में वृद्धि होने से खाद्य और विविध वस्तुओं का उत्पादन भी प्रभावित होगा। इस तरह लागत में वृद्धि से महंगाई बढ़ेगी, विदेश जाना भी महंगा होगा, लेकिन आइटी तथा फार्मा को लाभ होगा।

- बीएल शर्मा 'अकिंचन' उज्जैन

ट्रंप की वापसी

विवादास्पद आकांक्षाएं

डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर कब्जा करने, ग्रीनलैंड पर दावा करने तथा पनामा नहर पर पुन: नियंत्रण करने की योजनायें बनाई हैं। निर्वाचित अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने मार-ए-लागो में एक प्रेस कान्फ्रेंस में अपनी विवादास्पद क्षेत्रीय महत्वाकांक्षायें प्रकट की हैं और दुनिया ने आश्चर्य से इनको देखा। कनाडा पर कब्जा करने, ग्रीनलैंड पर दावा करने, पनामा नहर को पुन: अपने नियंत्रण में लेने तथा मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के प्रस्तावों ने अमेरिकी नीति में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां पुन: उभरने की आशंका पर गंभीर चिन्ता प्रकट की है। हालांकि, ट्रंप की लफ्फाजी का संबंध उनकी 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' विचारधारा से है, पर उसके आक्रामक विस्तार से न केवल अंतरराष्ट्रीय, बल्कि घरेलू स्तर पर काफी जोखिम पैदा किया है। ट्रंप की लफ्फाजी की जड़ें संभावित आर्थिक लाभों, रणनीतिक सैनिक दृष्टिकोण तथा राष्ट्रवादी वीरता में निहित हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा पर निशाना लगा कर ट्रंप पूरे उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक में अमेरिकन प्रभुत्व स्थापित करने के साथ ही मध्य अमेरिका में चीनी प्रभाव का मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन उनका दृष्टिकोण जटिल भू-राजनीतिक यथार्थ का अति-सरलीकरण करता है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका व्यापार और रक्षा के माध्यम से कनाडा को सब्सिडी देता है और इस प्रकार वे उस पर कब्जे को आर्थिक और सुरक्षा उपाय बताते हैं। इसके बावजूद उनके दावों में गहरे परस्पर निर्भर व्यापार संबंधों तथा नाटो में कनाडा के योगदान को अनदेखा किया गया है। आर्कटिक

में ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व बहुत पहले से स्वीकार किया जाता है, खासकर इसलिए कि जलवायु परिवर्तन से नए जहाजरानी मार्ग खुल सकते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की ट्रंप की इच्छा वहां के संसाधनों के कारण है जिनका दोहन नहीं हुआ है। इसके साथ ही वह भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने के नाम पर पनामा नहर पर पुन: कब्जा करने के ट्रंप के बयान एक पुराने युग की याद दिलाते हैं जब अमेरिका लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप करता रहता था।

लेकिन चीन के नियंत्रण के बारे में उनके दावे बिना प्रमाण के हैं और इससे पनामा तथा अन्य क्षेत्रीय सहयोगी उससे अलग हो सकते हैं। ट्रंप का विस्तारवादी दृष्टिकोण संभावित परिणामों के खतरों से भरा है और वह उन लक्ष्यों को ही नुकसान पहुंचा सकता है जिनकी प्राप्ति का वे दावा कर रहे हैं। कनाडा और डेनमार्क जैसे नाटो सहयोगी इन दावों को सीधे अपनी संप्रभुता के लिए खतरे की तरह देखते हैं। ऐसी कार्रवाइयों से उन गठबंधनों पर दबाव पड़ सकता है जो अमेरिकन सुरक्षा तथा उसकी वैश्विक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेरिकन हस्तक्षेप से चिन्तित मैक्सिको और पनामा अन्य विश्व शक्तियों, जैसे चीन और रूस से संबंध बढ़ा सकते हैं ताकि अमेरिकन आक्रामकता का मुकाबला कर सकें। कब्जा या आर्थिक दबाव महत्वपूर्ण व्यापार संबंधों को बाधित कर सकता है जिससे कनाडाई आयातों और निर्यातों पर आधारित उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रीनलैंड के अधिग्रहण से आर्कटिक संसाधनों के लिए टकराव बढ़ सकता है जिसमें न केवल डेनमार्क, बल्कि रूस और नार्वे जैसे अन्य आर्कटिक देश शामिल हो सकते हैं। ट्रंप की योजनायें उनको कट्टर समर्थकों को एकजुट कर सकती हैं, पर इससे मध्यमार्गियों व निर्दलीयों के अलग-थलग होने का खतरा पैदा होगा। इस आक्रामकता व अलगाव वाली नीतियों से चिन्तित अमेरिकन विधि निर्माता इन विचारों का व्यावहारिक क्रियान्वयन रोक सकते हैं। संप्रभु राष्ट्रों पर कब्जे का कोई प्रयास अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा जिसकी निन्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ व अन्य वैश्विक संस्थाओं में होगी। ट्रंप के इरादे संभवत: रणनीतिक गणित तथा राजनीतिक नाटकीयता का मिश्रण हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दे कर वे पद पर आने के पहले अपना समर्थन आधार बढ़ाना चाहते हैं। उनको समझना चाहिए कि अब साम्राज्यवाद अतीत की चीज बन गई है।

दिल्ली में मुफ्त बिजली का यथार्थ

दिल्ली की बिजली कंपनियों द्वारा 'पावर परचेज़ एडजस्टमेंट कास्ट' में भारी कटौती इसके समय और आयाम पर सवाल उठाती है।

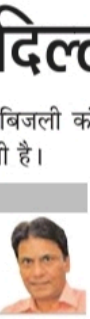

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

26 दिसंबर, 2024 को दिल्ली बिजली नियामक आयोग-डीईआरसी ने दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों-डिस्काम पर लागू 'पावर परचेज़ एडजस्टमेंट कास्ट'-पीपीएसी में कटौती की घोषणा कर दी। इन कंपनियों में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड-बीआरपीएल, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड-बीवाईपीएल तथा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड-टीपीडीडीएल शामिल हैं। 50 से 60 प्रतिशत की इन कटौतियों की समीक्षा जरूरी है। पीपीएसी तथा दिल्ली वालों के बिजली बिलों पर इसका प्रभाव समझने के लिए हमें कुछ मूल तत्वों पर गौर करना होगा।

डिस्काम से उपभोक्ताओं को उस दर पर बिजली सप्लाई की उम्मीद की जाती है जिसे डीईआरसी की सहमति प्राप्त हो। इसका निर्धारण इस आधार पर होता है कि दरों से बिजली खरीद के खर्च के साथ व्हीलिंग व वितरण का पूरा खर्च निकल आए। बिजली कानून, 2003 के अंतर्गत यह जरूरी है, लेकिन इसे विरले ही लागू किया जाता है। एक अत्यधिक जटिल व्यवस्था में 200 यूनिट प्रति माह खर्च करने वाले परिवारों से 3 रुपये प्रति यूनिट पैसा लिया जाता है जो औसत खर्च का लगभग आधा है। इस प्रकार 3 रुपये प्रति यूनिट का घाटा होता है। 44.6 प्रतिशत लेवी को जोड़ने पर यह कमी प्रति यूनिट 4.3 रुपये हो जाती है।

201 से 400 यूनिट प्रति माह खर्च करने वाले परिवारों से 4.5 रुपये प्रति यूनिट पैसा लिया जाता है जिससे प्रति यूनिट 1.5 रुपये का घाटा होता है। लेवी को शामिल करने पर यह 2.2 रुपये प्रति यूनिट हो जाता है। इस घाटे की भरपाई उद्योगों और बिजनेसों से ज्यादा पैसा लेकर होती है जिनको 18 रुपये प्रति यूनिट तक देना पड़ता है। विडंबना है कि उद्योगों और बिजनेसों से इतनी अधिक कीमत लेने के बावजूद 400 यूनिट प्रति माह से कम खर्च करने वाले परिवारों से होने वाले घाटा पूरा नहीं होता है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार उनसे केजरीवाल की 'खैरातों' के कारण 3 रुपये प्रति यूनिट मामूली पैसा भी नहीं लेना चाहती है।

डिस्काम से 200 यूनिट तक खर्च वाले परिवारों को बिल न देने तथा 400 यूनिट तक खर्च वाले परिवारों को 50 प्रतिशत छूट देने को कहा गया है जिसकी सीमा 800 रुपये प्रति माह है। हालांकि, सरकार इन सब्सिडी की भरपाई का वादा राज्य के बजट से करती है, पर इस वादे का पालन आमतौर से नहीं होता है। इससे डिस्काम का घाटा बढ़ जाता है जो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी से और गंभीर हो जाता है।

डिस्काम का बहुसंख्य उपभोक्ताओं से बिजली बिल तय करने का अधिकार नहीं हैं। वे बिजली चोरी रोकने के मामले में भी असहाय सिद्ध होती हैं क्योंकि बिजली चोरों को राजनेताओं का समर्थन मिलता है। डिस्काम केवल उद्योगों और बिजनेसों तथा 400 यूनिट से अधिक खर्च वाले परिवारों की बिजली दरें तय कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। इसके परिणामस्वरूप बिजली बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व कभी खर्च की भरपाई नहीं कर पाता है। यह समस्या अधिकांश डिस्काम के साथ है जहां राज्य बेलगाम होकर बिजली 'खैरातें' बांटते हैं तथा बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की अनुमति देते हैं। दिल्ली इस सूची में सबसे ऊपर है। डिस्काम की सहायता के लिए बिजली मंत्रालय ने 9 नवंबर, 2021 को एक आदेश दिया जिसमें डिस्काम पीपीएसी नामक सरचार्ज लगाने का प्राविधान था। इसे बिजली बिल की 'कुल ऊर्जा खर्च और फिक्स चार्ज कंपोनेंट' के प्रतिशत के रूप में तय किया गया। पीपीएसी का उद्देश्य बिजली खरीद खर्च में ईंधन मूल्यों के परिवर्तन से निपटना है। डिस्काम को हर तिमाही यह चार्ज लगाने की अनुमति मिली है। बीवाईपीएल के मामले में 20 दिसंबर, 2024 तक लागू पीपीएसी 32.27 प्रतिशत था। यह दूसरी तिमाही में बिजली खरीद खर्च के आधार पर है।

इससे डिस्काम को 21 दिसंबर, 2024 से 20 मार्च, 2025 तक तीन महीनों के लिए अतिरिक्त 5.95 प्रतिशत प्राप्त करने का अधिकार मिला है। इसके परिणामस्वरूप बीवाईपीएल का वर्तमान पीपीएसी 38.12 प्रतिशत था। इसी प्रकार नियामक ने बीआरपीएल के लिए 35.83 प्रतिशत तथा टीपीडीडीएल के लिए 36.33 प्रतिशत तय किया। लेकिन 26 दिसंबर, 2024 को डीईआरसी की 'अप्रत्याशित' घोषणा के परिणामस्वरूप पीपीएसी ने बीवाईपीएल का पीपीएसी घटा कर 13.62 प्रतिशत कर दिया जो 65 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार बीआरपीएल का पीपीएसी घटा कर 18.19 प्रतिशत किया गया जो 50 प्रतिशत से ज्यादा कम है। इसके साथ ही टीपीडीडीएल का पीपीएसी 20.52 प्रतिशत किया गया जो 45 प्रतिशत कम है। डिस्काम के पीपीएसी में यह कटौती किसी तर्क से परे है। दिसंबर, 2024 में पीपीएसी 38.12 प्रतिशत था जिसमें 5.85 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। यह 30 सितंबर, 2024 तक डेटा पर आधारित था। फिर नियामक द्वारा सरचार्ज में लगभग दो तिहाई कमी करने जैसी असाधारण घोषणा का क्या औचित्य है? यह विश्वास करना मूर्खतापूर्ण है कि बिजली खरीद के खर्च में इतनी कमी आई है। वैसे भी पीपीएसी में परिवर्तन उपलब्ध डेटा में कमी के बावजूद हुआ है। इससे इस संभावना को बल मिलता है कि पीपीएसी में भारी कटौती दिल्ली चुनावों को देख कर की गई है और चुनाव समाप्त होने के बाद इस निर्णय को उल्टा जा सकता है। यह विश्वास करने का भी कारण है कि यह राहत अस्थाई और भ्रामक है।

इसका संबंध डिस्काम की बैलेंसशीट में मौजूद तथाकथित रेगुलेटरी असेट्स-आरए से है जो वर्तमान समय में 27,200 करोड़ हैं। आरए उस समय बनते हैं जब डीईआरसी यह स्वीकार करती है कि टैरिफसे खरीद का खर्च पूरा नहीं होता है, पर दरें नहीं बढ़ाई जाती हैं। इस प्रकार दरें न बदलने के कारण होने वाली राजस्व में कमी को डिस्काम से प्राप्ति योग्य माना जाता है और इसे आरए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिजली कानून, 2003 तथा नेशनल पावर टैरिफ पालिसी-एनपीटीपी ने कठोरता से आरए पर प्रतिबंध लगाया है। इन दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'टैरिफ से खर्च प्रकट होने चाहिए तथा नियामक असेट नहीं बनाए जाने चाहिए।' दिसंबर, 2022 में विद्युत मंत्रालय ने आरए बनाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। लेकिर इसके बावजूद आरए बनाए गए। खातों में भारी मात्रा में आरए बनने के बाद अब डिस्काम यह पैसा वसूल करने के सारे प्रयास कर रही हैं। इसके लिए वह राजस्व में होने वाली कमी दूर करने के लिए बिजली दरें काफी अधिक बढ़ाने की अनुमति चाहती हैं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जिसने 2023 में ही एक आदेश से डीईआरसी को डिस्काम से उनका आरए वसूल करने को निर्देशित किया था।

यदि डीईआरसी इस पर अमल करती तो बिजली दरों में 100 प्रतिशत वृद्धि हो सकती थी। इसलिए उसने इस आदेश को चुनौती दी और वर्तमान समय में मामला अदालत में लंबित है। संक्षेप में कहा जाए तो डिस्काम अधिकांश उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी, बिजली चोरी के प्रति संवेदनहीनता तथा दरें बढ़ाने में अनियमितताओं के कारण लगातार भारी घाटे का शिकार बनती हैं। इस घाटे की भरपाई उद्योगों, बिजनेसों तथा ज्यादा बिजली खर्च करने वाले परिवारों से 'ज्यादा भुगतान के दबाव' से भी नहीं की जा सकती है। जब तक इन मूलभूत विकृतियों से निपटने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं पैदा होती है तब तक दिल्लीवासियों को भारी बिजली बिलों से कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

डिजिटल कनेक्टिविटी के नकारात्मक पहलू

> डूमस्क्रॉलिंग एक आधुनिक प्रघटना है जो डिजिटल कनेक्टिविटी के अंधेरे पक्ष को दर्शाती है।

शाइनी शर्मा
(लेखिका, शिक्षाविद हैं)

स्मार्टफोन और 24/7 सूचना तक पहुंच के निरंतर कनेक्टिविटी के युग में, लोगों द्वारा सूचना का उपभोग करने का तरीका काफी बदल गया है। हालांकि इससे कई लाभ हुए हैं, जैसे कि त्वरित संचार और ज्ञान के भंडार तक पहुंच, लेकिन इसने डूमस्क्रॉलिंग जैसे चिंताजनक व्यवहार को भी जन्म दिया है। यह शब्द नकारात्मक समाचारों को अंतहीन रूप से देखने की बाध्यकारी आदत को संदर्भित करता है, विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। यह नकारात्मक समाचारों और सूचनाओं को अत्यधिक स्क्रॉल करने का कार्य है, जो अक्सर चिंता, निराशा और असहायता की भावनाओं को जन्म देता है। यह घटना हाल के वर्षों में, विशेष रूप से वैश्विक संकटों के दौरान, तेजी से प्रचलित हो गई है और मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और सामाजिक कल्याण पर इसके प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। जबकि सूचित रहना जिम्मेदार नागरिकता का एक अनिवार्य पहलू है, डूमस्क्रॉलिंग का अभ्यास अक्सर परेशान करने वाली सामग्री के साथ अस्वस्थ व्यस्तता को जन्म देता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और समग्र कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। डूमस्क्रॉलिंग मानव मस्तिष्क की खतरों और नकारात्मक उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से उपजा है। यह विकासवादी विशेषता जिसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह के रूप में बेहतर जाना जाता है, ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व के लिए आवश्यक थी।

हालांकि, डिजिटल युग में, इसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और समाचार एल्गोरिदम के डिज़ाइन द्वारा बढ़ाया गया है, जो जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए सनसनीखेज और भावनात्मक रूप से चार्ज की गई सामग्री को प्राथमिकता देते हैं। जैसे ही उपयोगकर्ता अपने फ़ीड को स्क्रॉल करते हैं, उन्हें परेशान करने वाली हेडलाइन, ग्राफ़िक इमेज और ध्रुवीकरण

करने वाली राय की एक अंतहीन धारा का सामना करना पड़ता है, जिससे एक फीडबैक लूप बनता है जो उन्हें बांधे रखता है। डूमस्क्रॉलिंग मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख तरीकों में से एक है डोपामाइन पर इसका प्रभाव, जो आनंद और पुरस्कार से जुड़ा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डिजिटल सामग्री से जुड़ने पर, नकारात्मक सामग्री भी डोपामाइन का संक्षिप्त उछाल प्रदान करती है, इसके बाद होने वाला भावनात्मक तनाव व्यक्ति को थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करा सकता है। स्क्रॉलिंग के माध्यम से त्वरित डोपामाइन हिट की तलाश करने का यह चक्र आदत को मजबूत करता है, जिससे इसे रोकना मुश्किल होता जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के अलावा, यह उत्पादकता और जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। इस आदत से टालमटोल की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, क्योंकि व्यक्ति उन मुद्दों के बोझ से दब जाता है, जिनके बारे में वह पढ़ रहा होता है, जिससे उसे अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। समय के साथ, यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को खराब कर सकता है, साथ ही व्यक्तिगत विकास में भी बाधा डाल सकता है। व्यापक स्तर पर, डूमस्क्रॉलिंग के प्रचलन का सामाजिक कल्याण पर भी प्रभाव पड़ता है। विभाजनकारी और भय पैदा करने वाली सामग्री के लगातार संपर्क में रहने से राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण गहरा सकता है, क्योंकि लोग अपनी मौजूदा मान्यताओं को मजबूत करने वाले इको चैंबर में फंस जाते हैं। यह विखंडन सामूहिक कार्रवाई और नागरिक विमर्श को कमजोर करता है, जिससे समाज के लिए जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना मुश्किल हो जाता है। डूमस्क्रॉलिंग को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्तर पर, डिजिटल माइंडफुलनेस का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है।

इसमें स्क्रीन टाइम के लिए सीमाएँ निर्धारित करना, प्रतिष्ठित स्रोतों को प्राथमिकता देने के लिए अपने न्यूज़ फ़ीड को क्यूरेट करना और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होना शामिल है, जैसे व्यायाम, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना। सकारात्मक प्रगति और कार्रवाई योग्य कदमों को उजागर करने वाली समाधान-उन्मुख समाचार सामग्री की तलाश करने की आदत विकसित करना भी असहायता की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। सनसनीखेज सामग्री के बजाय संतुलित और रचनात्मक सामग्री को प्राथमिकता देने वाले एल्गोरिदम को डिज़ाइन करके, ये प्लेटफ़ॉर्म एक स्वस्थ डिजिटल वातावरण बना सकते हैं। मीडिया साक्षरता और भावनात्मक लचीलापन सिखाने वाली शैक्षिक पहल उपयोगकर्ताओं को डिजिटल परिदृश्य को जिम्मेदारी से नेविगेट करने के लिए और अधिक सशक्त बना सकती है। जबकि यह गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का दोहन करता है, मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और समाज पर इसके प्रभाव दूरगामी हैं। जागरूकता को बढ़ावा देने और इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रणनीतियों को लागू करने से, व्यक्ति और संस्थान प्रौद्योगिकी और सूचना के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसा करने में, वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि डिजिटल युग मानव कल्याण को कम करने के बजाय बढ़ाए।

आप की बात

कांग्रेस की तत्परता

सही बात है सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी को फिर से अपने आप में मंथन करने के लिए ऐसी तत्परता दिखानी चाहिए जो दिल्ली विधानसभा में इस बार दिखा रही। ऐसी मेहनत अगर वह हर एक चुनाव में करतीं तो आज विपक्ष में उसकी मजबूरी कुछ और होती। क्योंकि राजनीतिक दलों का गठबंधन की एकता कभी भी सुरक्षित रहतीं हैं क्योंकि मतभेद और आपसी खींचतान से गठजोड़ सुरक्षित नहीं रहता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेला ही लड़ने का फैसला किया।अब वह त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत मजा आयेगा। सहयोगी दलों से मिलनसार व्यवस्थाओं से पस्त होने के कारण उसे हार का आईना देखना पड़ा। कांग्रेस के पुननिर्माण का व जीर्णोद्धार जो प्रयास अब कर रहे हैं इससे कांग्रेस फिर अपने पेरों पर खड़ी हो शकित है बस उसे अतिउत्साह व घमंड से दूर रहते हुए कांग्रेस पार्टी अपने आप को तरसने हेतु सक्रियता से कार्य करें तो दिल्ली चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद फिर सत्ता पर आने हेतु परिश्रम एक नई दिशा दिखा सकता है बस उसे थोड़ा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जन-जन तक अपनी सकारात्मक सोच को पहुंचना होगा। दिल्ली की सत्ता में उसे पक्ष मिलें या विपक्ष वह फिर से पूरे भारत में इसी तरह अकेले आगे बढ़े तो एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।

- **हरिहर चौहान**, इंदौर

मौसम विभाग में नई क्रांति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में, भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम और मौसम विभाग विजन 2047 का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है और भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में मजबूत आधारशिला रखती है। मौसम विभाग विजन 2047 का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में विभाग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और प्रभावशाली बनाना है। यह नई तकनीकों को अपनाने, उन्नत अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। यह प्रयास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सटीक मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराकर किसानों, मछुआरों और आम जनता को लाभान्वित करेगा। साथ ही, मिशन मौसम आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने मौसम और वाणी जैसे एप्स की भी घोषणा की, जो मौसम से जुड़ी जानकारी तुरंत प्रदान करेंगे। यह पहल दर्शाती है कि सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्राथमिकता देकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रही है। मौसम विभाग विजन 2047 आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल उपहार है, और प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की सराहना करना निस्संदेह उचित है।

- **आर के जैन**, बड़वानी, मप्र

धर्मनगरी में शराबबंदी

धार्मिक नगरों में शराबबंदी की खबर सुर्खियों में आई। सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत निर्णय कई धार्मिक नगरों में शराबबंदी से देश-दुनिया से धार्मिक नगरी में आने वाले भक्तों को धार्मिक दृष्टि से उठाए गए निर्णय से धार्मिक नगरी को एक अच्छा संदेश जाएगा।इस तरह से मप्र सरकार द्वारा जागृति लाना ही ऐसे प्रयासों को सार्थकता प्रदान कर सकता है साथ ही आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को दूर कर एक स्वस्थ्य जीवन प्रदान कर सकता है। शराब के सेवन से होने वाला नुकसान हमारी कल्पना से कहीं अधिक घातक और जानलेवा होता है। खास तौर से युवाओं के बीच नशीले पदार्थों के सेवन का बढ़ता चलन अब एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है।किसी भी प्रदेश का भविष्य और तरक्की वहां के युवाओं पर टिकी होती है। देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चली जाए तो निश्चित तौर पर उनका जीवन अंधकारमय हो सकता है। नशे का मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी बुरा असर पड़ता है। यदि व्यक्ति अपनी,अपनों की एवं सारे संसार की खुशहाली जिंदगी चाहता है तो उसे आज से ही नशे का सेवन बंद कर देना चाहिए। दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। अपनी व अपने परिवार की खुशहाली के लिए नशे से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ताकि धार्मिक नगरी में अच्छे सन्देश से जागृति आ सके।

- **संजय वर्मा**, मनावर, मप्र

और कितना भुगतना बाकी?

आतंकवाद किसी भी कीमत पर मानवता के हित में नहीं है।इसका नैतिक समर्थन भी संबोधित देश के लिए भी घातक साबित हुआ है। ओसामा बिन लादेन को बढ़ावा देने में जितना फायदा अमेरिका को नहीं मिला अल-कायदा के 9/11 जैसे हमलों में उससे कहीं अधिक उसे भुगतना पड़ा है।उस आतंकवाद से मुक्ति के लिए अमेरिका को एक लंबा और महंगा युद्ध लड़ना पड़ा जिसमें हजारों सैनिकों की जान और ट्रिलियनों डॉलर का आर्थिक नुकसान भी उसके हिस्से आया। ठीक उसी तरह तालिबान भी पाकिस्तान के गले की घंटी बन चुका है। तालिबान पाकिस्तान में उग्रवाद, अस्थिरता, और आतंकवादी हमलों का पर्याय बन कर एक गंभीर चुनौती बन गया है। इससे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने को लेकर पाकिस्तान रसातल में जाता दिखाई दे रहा है।आतंकवाद का खूब लालन पालन पाकिस्तान के लिए बूमरैंग साबित हो रहा जो लौटकर उसी पर हमलावर है। लंबे समय तक आतंकवाद का समर्थन करने से इन दोनों देशों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हालत संकटों से घिरी हुई है। अमेरिका को तो बात समझ आ गई है।

- **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

अमेरिका की मुद्रास्फीति के अनुमान से पूर्व सोना-चांदी में सतर्कता

हमारे प्रतिनिधि

राजकोट। अमेरिकी डालर तथा बॉण्ड के प्रतिफल में गिरावट के कारण सोने का भाव सुधरकर विश्व बाजार में २७०० डालर प्रति औंस के स्तर पर पहउनच गया। चांदी सहेज बढकर ३०.०९ डालर रहा। अमेरिका की मुद्रास्फीति का आंकडा घोषित हो इसका इंतजार है। मुद्रास्फीति के आधार पर आगामी महीनों की वित्त नीति की स्पष्टता होने से उत्सुकता बढी है।

अमेरिकी डालर इन्डेक्स दो वर्ष के टाप से घटा था और १० वर्ष का बाण्ड प्रतिफलभी घटा है। अमेरिका के कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स की घोषणा होने वाली है।धारणा यह यह है कि नवंबर २०२४-२५ में २७ प्र. श. था वह बढकर २.९ प्र. श. आना चाहिए। मासिक स्तर पर इसमें ०.३ प्र. श. की वृद्धि हो सकती है।

राजकोट झवेरी बाजार में २४ कैरेट शुद्ध सोने का भाव प्रति १० ग्राम २०० रु. के सुधार से ८०५०० रु. और मुंबई में ३९६ रु. बढकर ७८४२४ रु. रहा। चांदी राजकोट में प्रति किल.ो ९०५०० रु. पर स्थिर रहा। मुंबई में ८२० रु. बढने से ८०५५० रु. रहा।

एमसीएक्स पर रु.५,०३,३३५ करोड़ का ऑल टाईम हाई टर्नओवर दर्ज हुआः क्रूड ऑयल ऑप्शंस में रु.४,११,२६५ करोड़ का कारोबार

सोने की वायदा कीमतों में ३५४ रुपये और चांदी वायदा में ६०४ रुपये का ऊछालः क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट १३ रुपये की नरमीः बुधवार को कमोडिटी वायदाओं में १०६७२.१७ करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में ११८५०८.५७ करोड़ रुपये का टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में ५३२१.२८ करोड़ रुपये का कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स १९०७२ पॉइंट के स्तर पर

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर सोमवार, १३ जनवरी को रु.५,०३,३३५ करोड़ का ऑल टाईम हाई टर्नओवर दर्ज हुआ। इसके साथ ही क्रूड ऑयल के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में रु.४,११,२६५ करोड़ का कारोबार हुआ, जो ट्रेडरो का कमोडिटी वायदा पर के ऑप्शंस में विशेष रूचि को दर्शाता है।

बुधवार, १५ जनवरी को शाम पांच बज़े तक में कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में १२९१८१.४१ करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में १०६७२.१७ करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में ११८५०८.५७ करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स जनवरी वायदा १९०७२ पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर १२६३.८७ करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में ५३२१.२८ करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में ७८३२५ रुपये पर खूलकर, ७८६८७ रुपये के दिन के उच्चा और ७८२४१ रुपये के नीचले स्तर को छूकर, ७८१५६ रुपये के पिछले बंद के सामने ३५४ रुपये या ०.४५ फीसदी की मजबूती के साथ ७८५१० रुपये प्रति १० ग्राम बोला गया। इनके अलावा गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा ३०३ रुपये या ०.४८ फीसदी की मजबूती के साथ ६३२८३ रुपये प्रति ८ ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा ३७ रुपये या ०.४८ फीसदी की बढ़त के साथ ७८०६ रुपये प्रति १ ग्राम हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा ७८३२३ रुपये पर खूलकर, ७८६५० रुपये के दिन के उच्चा और ७८२२८ रुपये के नीचले स्तर पर पहुंचकर, ३३५ रुपये या ०.४३ फीसदी की तेजी के संग ७८४८६ रुपये प्रति १० ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में ९०८६० रुपये पर खूलकर, ९१४२० रुपये के दिन के उच्चा और ९०५१० रुपये के नीचले स्तर को छूकर, ९०५५६ रुपये के पिछले बंद के सामने ६०४ रुपये या ०.६७ फीसदी की मजबूती के साथ ९११६० रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा ५९१ रुपये या ०.६५ फीसदी की बढ़त के साथ ९११९६ रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा ५८८ रुपये या ०.६५ फीसदी की मजबूती के साथ ९१२०७ रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में १५०२.४५ करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा २.६५ रुपये या ०.३२ फीसदी की मंदी रही और यह कॉन्ट्रैक्ट ८२६.९ रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि जस्ता जनवरी वायदा ३.३ रुपये या १.२१ फीसदी गिरकर २७०.३५ रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा ८५ पैसे या ०.३४ फीसदी की नरमी के साथ २४६.१ रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा १.३५ रुपये या ०.७६ फीसदी की गिरावट के साथ १७६.३५ रुपये प्रति किलो के भाव से कारोबार हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में ३९९५.९८ करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में ६७२६ रुपये पर खूलकर, ६७८१ रुपये के दिन के उच्चा और ६६८० रुपये के नीचले स्तर को छूकर, १३ रुपये या ०.१९ फीसदी औंधकर ६७२३ रुपये प्रति बैरल बोला गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा १२ रुपये या ०.१८ फीसदी घटकर ६७२६ रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा ३३८.९ रुपये पर खूलकर, ३४९.१ रुपये के दिन के उच्चा और ३३४.२ रुपये के नीचले स्तर पर पहुंचकर, ३४८.३ रुपये के पिछले बंद के सामने ३.७ रुपये या १.०६ फीसदी की गिरावट के साथ ३४४.६ रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा ३.६ रुपये की मंदी रही और यह कॉन्ट्रैक्ट ३४४.५ रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा ९२८ रुपये पर खूलकर, २.४ रुपये या ०.२६ फीसदी की गिरावट के साथ ९२४ रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। कॉटन कैंडी जनवरी वायदा ८० रुपये या ०.१५ फीसदी घटकर ५४४०० रुपये प्रति कैंडी हुआ।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 16 जनवरी 2025

भरोसे लायक नहीं मार्क

फेसबुक की ओनर कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग एक बार फिर गलतबयानी के मामले में फंस गए हैं। संसद की आईटी एंड कम्युनिकेशन मामलों की स्टैंडिंग कमिटी उन्हें समन करने वाली है। फेसबुक और मेटा पहले भी तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और फेकन्यूज को लेकर ढिलाई जैसे आरोपों में घिरती रही हैं।

क्या है मकसद | यह वाकई हैरत की बात है कि जकरबर्ग ने भारत को भी उन देशों में शामिल कर लिया जहां पिछले साल चुनाव में सरकारों ने सत्ता गंवाई। तथ्य यह है कि बीजेपी की सीटें भले कम हुई हों, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन NDA ने बहुमत हासिल कर सरकार में वापसी की। परिणामस्वरूप नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार चल रही है। इस तथ्य से जकरबर्ग कैसे अनजान हो सकते हैं? क्या वह जानबूझकर भारत सरकार के बारे में गलत सूचनाएं फैला रहे हैं?

मेटा चीफ की गलतबयानी

विश्वसनीयता का सवाल | जकरबर्ग ने अभी हाल ही में मेटा की कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लाए जा रहे इन बदलावों के तहत मेटा थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग का सिस्टम समाप्त करने वाली है। उसकी इस घोषणा को भी अमेरिका में हो रहे सत्ता परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह ट्रंप समर्थकों को खुश करने की कोशिश है जो फ्री स्पीच के नाम पर फैक्ट चेकिंग की इस व्यवस्था का काफी समय से विरोध कर रहे हैं। 2018 में सामने आए कैंब्रिज एनालिटिका विवाद को भी इस संदर्भ में याद किया जा सकता है जिसमें यूजर्स के पर्सनल डेटा की सुरक्षा का सवाल प्रमुखता से उभरा था।

गैर जिम्मेदारी स्वीकार्य नहीं | ऐसे और भी मामले हैं जिनसे यह संदेह मजबूत होता है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल सिर्फ अधिक से अधिक मुनाफा हासिल करने के मकसद से हो रहा है। समाज को होने वाले नुकसान की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस तरह की गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

व्यापक चिंता | ताजा विवाद को सरकार ने गंभीरता से लिया है, यह अच्छी बात है। लेकिन जरूरी है कि चिंता इसी मामले तक सीमित न रहे। हेट स्पीच और फेक न्यूज के अन्य मामले भी उतने ही गंभीर हैं चाहे वे किसी भी समुदाय और पार्टी के खिलाफ केंद्रित हों। उम्मीद है, सरकार की सख्ती मेटा को ज्यादा जिम्मेदार बनाएगी।

साझी दिल्ली

आओ चलें नारायणा

विवेक शुक्ला

नारायणा, पालम और झारेरा गांवों का दिल्ली कैंट से गहरा नाता है। इन तीनों गांवों की भूमि के कुछ हिस्सों को अधिग्रहित करके दिल्ली कैंट विकसित किया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोहड़ी मनाने नारायणा गांव जा रहे होंगे तो उन्हें अपने दिवंगत मित्र अरुण जेटली का भी ख्याल आ रहा होगा। उनका घर नारायणा में ही था। दिल्ली कैंट का निर्माण 1914 और 1920 के बीच हुआ था। कोलकाता से देश की राजधानी दिल्ली में 1911 में शिफ्ट हुई, तब ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली कैंट विकसित करने का फैसला किया। फिर कैंट के लिए पालम, झारेरा और नारायणा की जमीनें ली गईं। अगर आप नारायणा के किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वह बताएंगे कि दिल्ली कैंट उनके गांव की जमीन पर आबाद है। दिल्ली कैंट के निर्माण के वक्त ही यहां पर सेंट मार्टिन गैरिसन चर्च भी तामीर होने लगा था। इस तरह के डिजाइन का चर्च कम से कम राजधानी में और कहीं नहीं मिलेगा। डिजाइनर आर्थर गार्डन शूस्मिथ ने बनाया था इसका डिजाइन। इसके दरवाजे बड़े नहीं हैं। इसके निर्माण यह था कि कैंट क्षेत्र में रहने वाले सैनिकों को प्रार्थना करने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े।

जिसे बरार स्क्वायर कहा जाता है, वह लगभग सारा क्षेत्र नारायणा गांव में ही था। नारायणा के लिए कहा जाता है कि यह राजधानी के सबसे प्राचीन गांवों में से एक है। इसकी पहचान तोमर जाटों के गांव के रूप में होती है। दिल्ली के सब गांवों में एक बात समान मिलेगी। इनमें एक जाति बहुमत में होती है और बाकी सर्व समाज भी इधर रहता है। यहां जाटों, गुर्जरों, यादवों के सर्वाधिक गांव हैं। कुछ गांव त्यागी और ब्राह्मण के भी हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद, दिल्ली के शहरीकरण के साथ नारायणा गांव में भी बदलाव आया। इसके आसपास पॉश नारायणा कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया और डीडीए फ्लैट्स बने। नारायणा कॉलोनी में अरुण जेटली के पिता का भी घर था। जब जेटली DU में पढ़ रहे थे, नारायणा में ही रहा करते थे। जब देश में इमरजेंसी लगी तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके नारायणा वाले घर ही पहुंची थी। हालांकि वे पुलिस को चकमा देकर निकल गए थे।

एकदा

असली ख़ज़ाने का पता

संत कबीर एक गांव से होकर गुजर रहे थे। तभी एक विद्वान उनके पास आया और कहा, 'कबीर, तुम्हारी शिक्षाएं ठीक हैं, लेकिन क्या तुमने कभी वेदों का अध्ययन किया है? क्या तुम हमारे धार्मिक कर्मकांडों में भाग लेते हो? हमारे पुरखे कहते थे कि वेदों का अध्ययन किए बिना व्यक्ति को कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।' कबीरदास ने सहज रहते हुए और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, 'वेद और शास्त्र केवल शब्दों में होते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान तो भीतर है। भगवान हर जगह हैं, और उनका साक्षात्कार हमारे भीतर से ही संभव है। अगर तुम्हें सच्चाई और ज्ञान चाहिए तो उसे बाहर से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से खोजो।' यह सुनकर उस विद्वान को गुस्सा आ गया। उसने कहा, 'तुम यह कह रहे हो कि मैं बिना वेदों के ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं?' कबीर मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, 'कल्पना करो, एक व्यापारी अपने घर में खजाना रखे हुए है, और वह पूरे गांव में उसे तलाशने के लिए दौड़ता है। क्या ऐसा संभव है?' 'नहीं, क्योंकि वह खजाना उसी के घर में पड़ा हुआ है।' विद्वान ने जवाब दिया। कबीरदास इस पर मुस्कुरा उठे और कहा, 'ठीक, इसी तरह जो सत्य और ज्ञान तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है।' कबीर की यह बात उस विद्वान को समझ आ गई।

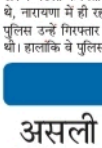

Subrata Dhar

संकलन : रिंकल शर्मा

SBI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश में ग़रीबी घट रही, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है

इस देश से ग़रीबी जाएगी कितने साल में

सुदीप ठाकुर

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में गरीबी लगातार घट रही है। 2023 से 2024 के एक साल के दौरान इसमें करीब 3% की कमी आई है। यह राहत देने वाली खबर है, लेकिन यह पूरी खबर नहीं है। इस रिपोर्ट में सालाना घरेलू उपभोग खर्च सर्वे (HCES) के अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के आंकड़ों का उपयोग कर दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 24 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी महज 4.86% रही। वित्त वर्ष 23 में यह 7.2% थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में गरीबी 4.6% से घटकर 4.09% रह गई।

अधूरे आंकड़े | इस आंकड़े में एक पेच है, जिसने रोजाना खर्च के व्यावहारिक पक्ष को लेकर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। SBI रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,632 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,944 रुपये प्रतिमाह की नई गरीबी रेखा का अनुमान है। दशकीय महंगाई दर और सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर यह मानक बनाया गया है। इसका मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजाना 54.4 रुपये और शहरी क्षेत्र में 64.8 रुपये आय को गरीबी की रेखा माना गया है। इस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल अमूल या मदर डेयरी का एक लीटर टोंड दूध खरीदा जा सकता है, जबकि शहरी क्षेत्र में इतने में एक लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा।

समिति पर सवाल | तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को लेकर शुरू से सवाल उठे हैं। UPA सरकार के समय, 2005 में गठित इस समिति ने सबसे पहले 2009 में पेश अपनी रिपोर्ट में परचेजिंग पॉवर पैरिटी (पीपीपी) यानी क्रय शक्ति समता को गरीबी आंकने का पैमाना बनाया। उनकी परिभाषा में स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए जाने वाले निजी खर्च को भी गरीबी के आकलन का आधार बनाया गया।

डेटा का खेल | तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 446.68 रुपये मासिक और शहरी क्षेत्र के लिए 578.8 रुपये मासिक से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना। यानी ग्रामीण क्षेत्र में रोजाना 14.88 और शहरी क्षेत्र में रोजाना 19.29 रुपये! इस आकलन के मुताबिक 2004-05 में करीब 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे।

आयोग की आलोचना | तेंदुलकर समिति के आकलन की तीखी आलोचनाओं के बीच योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इससे खुद को अलग कर लिया था। तेंदुलकर समिति के पैमाने से 2011-12 में गरीबी घटकर 21.9% रह गई। तब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27.20 रुपये रोजाना और शहरी क्षेत्रों के लिए 33.33 रुपये रोजाना आय को गरीबी रेखा माना गया।

बहस अब भी जारी | बीते आठ दशकों में गरीबी की परिभाषाओं को लेकर तीखी बहस चलती रही है। 15 अगस्त 1947 से तुलना करें, तो निश्चित रूप से देश ने गरीबी पर बड़ी विजय हासिल की है। 1971 में इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' नारे ने गरीबी को सियासत के केंद्र में ला दिया और आज भी यह सामाजिक-आर्थिक के साथ सियासी मुद्दा भी है। मुश्किल यह है कि गरीबी की परिभाषा दिल्ली के नीति नियंताओं के गलियारों में उलझती रही है।

सही तस्वीर नहीं | चूंकि 2011 से जनगणना नहीं हुई है, लिहाजा आय पर आधारित गरीबी के ताजा वास्तविक आंकड़े भी नहीं मिले हैं। गरीबी का मौजूदा गणित NFHS-5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य-5) के सर्वे पर भी टिका हुआ है। NFHS-5 को दो चरणों में किया गया। पहला कोविड से पहले और दूसरा उसके बाद। जाहिर है, कोविड ने पूरी तस्वीर बदल दी। लिहाजा यह भी माना गया कि इसके आंकड़े बहुआयामी गरीबी की सही तस्वीर पेश नहीं करते।

एतराज उठ चुके | NFHS-5 के सर्वे के तरीके पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष (अब दिवंगत) बिबेक देबरॉय और सदस्य संजीव सान्याल तक ने एतराज किया था। इकॉनमिक टाइम्स में छपे अपने एक लेख में उन्होंने सवाल उठाया था कि सर्वे की प्रश्नावली में सिर्फ मच्छरदानी के बारे में पूछा गया, जबकि लोग मच्छर भगाने के लिए कॉइल, वेपोराइजर, क्रीम और स्प्रे वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं!

नई परिभाषा चाहिए | दरअसल, गरीबी के आंकड़ों और उसके आकलन को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। चाहे सरकार कोई भी रही हो। बेशक, खाद्य सुरक्षा कानून (2013), मनरेगा (2005), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (2024) जैसे कदमों से गरीबी से निपटने में मदद मिली है। लेकिन PGKAY के तहत यदि आज भी 83 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, तो यह गरीबी की बदतर स्थिति को ही दिखाता है। ऐसे में हमें गरीबी की एक नई परिभाषा की जरूरत है। अदम गोंडवी इस मौके पर याद आते हैं, *'जो उलझ कर रह गई है परिभाषाओं के जाल में/ इस देश से गरीबी जाएगी कितने साल में!'*

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सबके साझा विकास की गारंटी है सहकारिता

मुरलीधर मोहोल

हाल ही नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का वैश्विक सहकारी सम्मेलन हुआ। इसमें सौ से अधिक देशों से नेताओं की आमद एक सतत एवं न्यायसंगत भविष्य को आकार देने में सहकारी समितियों के बढ़ते महत्व का प्रमाण है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान आकर्षित कराना है।

सशक्त अध्याय | यह वर्ष वैश्विक, आर्थिक और सामाजिक विमर्श का वह महत्वपूर्ण अध्याय बन रहा है, जहां सहकारी समितियों को न केवल स्थानीय विकास के साधन बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भी पहचान दी जा रही है। भारत में सहकारी समितियां ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उदाहरण के लिए, अमूल ने न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया, बल्कि सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता और समृद्धि का प्रतीक भी बन गया है।

भारतीय भूमिका | भारत ने लंबे समय से आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में सहकारी समितियों के मूल्य को पहचाना है। नई दिल्ली में आयोजित ICA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आत्मनिर्भर, समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने की सहकारी क्षेत्र की क्षमता पर भी प्रकाश डाला, खासकर ग्रामीण भारत में जहां सहकारी समितियां कृषि और डेयरी फार्मिंग जैसे क्षेत्रों की रीढ़ बनी हुई हैं। सरकार द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम इस मान्यता को उजागर करते हैं कि सहकारी समितियां केवल अतीत की निशानी नहीं हैं, बल्कि समकालीन आर्थिक और सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

AI Image

कॉमन रूम

समस्याओं का हल | विश्व जब आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अशांति से जूझ रहा है तो सहकारिता विकास के लिए एक समावेशी, लोकतांत्रिक और लचीला मॉडल पेश करती है। सहकारी मॉडल का जोर एकजुटता, आपसी सहयोग और लोकतांत्रिक भागीदारी पर है, जो इसे प्रमुख वैश्विक समस्याओं को संबोधित करने के लिहाज से अद्वितीय बनाता है। सहकारी समितियां वित्तीय लाभ से अधिक लोगों की प्राथमिकताओं पर जोर देती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों के लाभ और व्यापक रूप से वितरित हों। सहकारिता आंदोलन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़कर भारत ने खुद को सतत और समावेशी विकास के वैश्विक अधिवक्ता के रूप में स्थापित किया है।

आगे की राह | सहकारिता सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 'सहकार से समृद्धि' के विजन से ही 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश को एक बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जहां विकास को साझा किया जाता है और असमानताओं को कम किया जाता है।

(लेखक केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

ख़ुशियों पर पहरा लगा देती है तुलना करने की आदत

देवेन्द्रराज सुथार

मनुष्य को छोड़कर सभी जीव अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते हैं। चींटियां अपने बिलों में रहती हैं और जरूरत के हिसाब से भोजन जुटाती हैं। पक्षी छोटे-छोटे घोंसले बनाकर खुशी से रहते हैं। पेड़-पौधे भी अपनी जरूरतों के हिसाब से बढ़ते हैं। लेकिन मनुष्य इस प्राकृतिक नियम के विरुद्ध जाता है। वह बार-बार अपनी जरूरतें बढ़ाता रहता है। कल तक जो विलासिता थी, आज वह जरूरत बन गई है। असीमित इच्छाओं की यह दौड़ उसे जीवन के असली आनंद से दूर ले जाती है।

आज का युग भौतिक समृद्धि का युग है। तकनीक ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसने हमारी इच्छाओं को भी बढ़ाया है। हर दिन नए-नए उत्पाद बाजार में आते रहते हैं। विज्ञापन लगातार हमें यह समझाते रहते हैं कि इन चीजों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम भूल जाते हैं कि इन चीजों को पा लेना ही खुशी की गारंटी नहीं है। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जरूरतें तय करने लगे हैं। किसी के पास नया फोन है तो हम भी वही चाहते हैं। किसी ने नई कार खरीदी है तो हम उसकी भी तलाश करने लगते हैं। तुलना करने की यह आदत हमें न सिर्फ मानसिक तनाव देती है, बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति को भी अस्थिर कर देती है।

हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और जीवन परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। दूसरों से प्रेरणा लेना बुरा नहीं, लेकिन दूसरों की नकल करना न केवल हमें मानसिक शांति से वंचित करता है, बल्कि वास्तविक लक्ष्य से भी भटका देता है। जरूरतों और चाहतों में बहुत फर्क होता है। जरूरतें वे होती हैं, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, जबकि चाहत हमारी लालसाओं और इच्छाओं का ही विस्तार है।

भारतीय संस्कृति में 'अपरिग्रह' का विशेष महत्व है। इसका अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हैं, तो हमारा मन भौतिक वस्तुओं के मोह से मुक्त हो जाता है। इससे हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। जापानी संस्कृति में 'minimalism' का विशेष महत्व है। जापान में लोग केवल उन्हीं चीजों को रखते हैं जो उनके जीवन में सार्थक योगदान देती हैं। हमें ऐसे दृष्टिकोण से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम समझ जाते हैं कि जीवन का आनंद चीजों की मात्रा में नहीं, बल्कि उनके सार्थक उपयोग में है, तो हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। जरूरतें जब सीमित होने लगेंगी, जीवन खुद-ब-खुद सरल, सुखद और सार्थक हो जाएगा। जीवन की खुशियों का रहस्य यही है।

एक दिन की राजधानी इलाहाबाद

उमेश चतुर्वेदी

सन 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो सका था। अंग्रेजों ने भारतीयों की क्रांति दबाने के लिए क्रूरता की हद पार कर दी। गांव के गांव जला दिए। लोगों को दंडित किया गया, जुर्माने की वसूली हुई। जिस पर भी आंदोलन में शामिल होने का थोड़ा सा शक हुआ, उसे अंग्रेजी हुकूमत ने बिना सुनवाई के फांसी पर चढ़ा दिया। हालांकि बगावत की आंच से लंदन भी नहीं बच पाया। अंग्रेजी कौम दुनिया में सबसे सभ्य समझी जाती थी, लेकिन उसने भारतीयों पर जो अत्याचार किए, उसने उनकी बदनामी करा दी। ब्रिटेन की तब की सरकार और महारानी विक्टोरिया ने तय किया कि भारत का शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। इसकी घोषणा कहां हो, इसके लिए काफी माथापच्ची हुई।

टाइम मशीन

दिल्ली सेफ नहीं थी | ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राजकाज कलकत्ता से चलाती थी। दिल्ली पर बेशक कंपनी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन यहां से लेकर मेरठ और आगरा तक स्वाधीनता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो चुका था। स्वतंत्रता सेनानियों ने इन सभी जगह अंग्रेजी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था।

अंग्रेजों के कब्जे में प्रयागराज | तब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था। उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था। यह शासन व्यवस्था के तौर पर महत्वपूर्ण शहर था। इसे क्रांतिकारियों का दुर्भाग्य कहें या अंग्रेजों का सौभाग्य कि इलाहाबाद पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार रहा।

सुरक्षित लगा इलाहाबाद | जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में लेना तय किया तो सत्ता हस्तांतरण के लिए जगह की खोज शुरू हुई। तब कंपनी की ओर से भारत का शासन संभाल रहे लॉर्ड कैनिंग ने सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा के लिए इलाहाबाद शहर को ही चुना। इस शहर के हक में यह बात भी गई कि यहां के किले में अंग्रेजी लाव-लश्कर ज्यादा महफूज था।

क्वीन के पास आई सत्ता | जिस दिन भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हुआ, वह तारीख थी 1 नवंबर 1858। इसी शहर के मिंटो पार्क में उन्होंने सत्ता हस्तांतरण का घोषणापत्र पढ़ा। सारी औपचारिकताएं यहीं हुईं और एक दिन के लिए समूचा राजकाज यहीं से चला। इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना।

राजधानी बनने का मौका | इलाहाबाद पहले अवध के नवाब के अधीन आता था। नवाब ने साल 1801 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इसका विकास कराया था। वे तो 1836 में इसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की राजधानी भी बनाना चाहते थे। लेकिन फिर आगरा को चुन लिया गया।

मुश्किलों के पार

प्रणव प्रियदर्शी

जहां चाह वहां राह- यही मूल मंत्र रहा है मोबिक्विक की को-फाउंडर और CFO उपासना टाकू का। मुश्किलों के पहाड़ के बीच से रास्ता निकालने की आदत उनकी शुरू से थी। यही देखिए कि उन्होंने ग्रैजुएशन किया था NIT जालंधर से, लेकिन सपना देखती थीं दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज मसलन स्टैनफर्ड या बर्कले में पढ़ने का। जब यह मुश्किल हल हुई और स्टैनफर्ड ने एडमिशन की उनकी अर्जी स्वीकार कर ली तब सवाल उठा कि पैसे कहां से आएंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। ऐसे में एक ही विकल्प था कि स्पॉन्सरशिप के लिए कोशिश की जाए। स्टैनफर्ड के सीनियर इंडियन स्टूडेंट्स से जुड़कर जितने भी संभावित स्रोत हो सकते थे, सबको खंगाल लिया। कहीं बात बनती नहीं दिख रही थी। लेकिन आखिरी पलों में Stanford Linear Accelerator Centre ने न केवल उनकी शिक्षा से जुड़े सारे खर्च उठा लिए बल्कि उनके लिए 2000 डॉलर का मंथली स्टाइपेंड भी मंजूर कर लिया। करियर आगे बढ़ा, उन्होंने HSBC और Paypal जैसी कंपनियों के साथ काम किया। लेकिन कुछ नया, कुछ अपना खड़ा करना था। उन्हें मालूम था कि भारत में फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल होता है। इस गैप को भरने के लिए वह हाथ-पैर मार रही थीं। इसी क्रम में बिपिन प्रीत सिंह से मुलाकात हुई। दोनों की राह मिली, जीवन मिला। आज दोनों मोबिक्विक तो चला ही रहे हैं, पति-पत्नी के तौर पर भी साथ हैं। नई लड़कियों के लिए उपासना की सलाह यही है कि न कभी बड़े सपने देखने में संकोच करो और न उसे सच करने की कोशिशों में कोई ढील आने दो।

उपासना टाकू

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

नया राजनीतिक माहौल

15 जनवरी के संपादकीय 'राज्य का दर्जा' में बिलकुल सही कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग के उद्घाटन के मौके पर कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे कहा जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर में एक नए राजनीतिक माहौल की शुरुआत हो सकती है। इस प्रकार के सहयोगात्मक राजनीतिक वातावरण से उम्मीद जताई जा सकती है कि केंद्र सरकार जल्दी ही जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. से उमर अब्दुल्ला के दूरी बढ़ाने के प्रयास में एक नए रिश्ते कहानी तो नहीं छुपी है?

देवाशीष गुप्ता, नोएडा

आस्था का बड़ा मेला

महाकुंभ को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में जाना जाता है। यह महापर्व भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां आस्था, विश्वास और श्रद्धा की अनूठी भावना देखने को मिलती है। तीर्थराज प्रयाग तीन पवित्र नदियों के संगम के लिए तो जाना ही जाता है, यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। यहां कुंभ का ऐसा भव्य आयोजन न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रगाढ़ करता है, बल्कि जातीय समरसता, सांस्कृतिक बोध और वैश्विक कल्याण के महत्व को भी उजागर करता है। ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते हैं, जब एक उद्देश्य से इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हों। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप छोड़ते हैं।

अमृतलाल मारू, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

डिजिटल पेमेंट में दिल्ली-मुंबई को मात दे रहे छोटे शहर - खबर

- छोटे शहरों में चिल्लर का टोटा तो नहीं हो गया!

मीनाक्षी शर्मा

[illegible]

देश का निर्यात दिसंबर में एक प्रतिशत घटकर ३८.०१ अरब डॉलर पर

नई दिल्ली : वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का वस्तु निर्यात दिसंबर, २०२४ में सालाना आधार पर करीब एक प्रतिशत घटकर ३८.०१ अरब डॉलर रह गया, जबकि व्यापार घाटा कम होकर २१.९४ अरब डॉलर रह गया। यह लगातार दूसरा महीना है जबकि निर्यात में गिरावट आई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, २०२४ में आयात सालाना आधार पर पांच प्रतिशत बढ़कर ५९.९५ अरब डॉलर हो गया। चालू वित्त वर्ष (२०२४-२५) के पहले नौ माह (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान निर्यात १.६ प्रतिशत बढ़कर ३२१.७१ अरब डॉलर और आयात ५.१५ प्रतिशत बढ़कर ५३२.४८ अरब डॉलर हो गया है। अप्रैल-दिसंबर के दौरान व्यापार घाटा यानी आयात व निर्यात के बीच का अंतर बढ़कर २१०.७७ अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो गत वित्त वर्ष २०२३-२४ की इसी अवधि में १८९.७४ अरब अमेरिकी डॉलर था। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने नवीनतम आंकड़ों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों में भारत का निर्यात अन्य देशों की तुलना में बेहतर चल रहा है। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, '' यह हमारे निर्यात की जुझारू क्षमता को दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष की सभी तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसंबर) में भी हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। हम पेट्रोलियम के अलावा निर्यात में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।'' मंत्रालय ने हाल ही में २० देशों में भारतीय दूतावासों की वाणिज्यिक शाखाओं के साथ बैठक की। इसमें निर्यात को प्रभावित करने वाले मुद्दों तथा उन्हें हल करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। इन २० देशों का भारत के निर्यात में करीब ६० प्रतिशत हिस्सा है। बर्थवाल ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में जिन क्षेत्रों ने निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की है उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और औषधि शामिल हैं। नवंबर, २०२४ के लिए सोने तथा चांदी के आयात के आंकड़ों में संशोधन के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने कहा कि सुसंगत आंकड़े प्रकाशित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने को समिति का गठन किया गया है। सरकार ने नवंबर, २०२४ के लिए सोने के आयात के आंकड़ों को संशोधित किया है। इसे पांच अरब अमेरिकी डॉलर घटाकर अब ९.८४ अरब डॉलर किया गया है। बर्थवाल ने कहा, '' आंकड़ों में संशोधन होता रहता है...हम आंकड़ों को जारी करने की वैश्विक प्रथाओं का पालन कर रहे हैं।''

भारत दो माह में २० प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा : गडकरी

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत अगले दो माह में २० प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। पेट्रोल के साथ एथनॉल मिश्रण का चलन २००१ में एक प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) के रूप में शुरू हुआ था। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा, द्रह्यस अगले दो महीनों में २० प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ई२० (२० प्रतिशत एथनॉल वाला पेट्रोल) के इस्तेमाल से प्रदूषण कम करने में मदद सह्रस्ह्रत्द्रह्य केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और हुंदै मोटर्स ने १०० प्रतिशत जैव-एथनॉल पर चलने वाले वाहनों का विनिर्माण शुरू कर दिया है। गडकरी ने कहा कि देश में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है क्योंकि दुनिया के ५० सबसे प्रदूषित शहरों में ४२ भारत में हैं। उन्होंने कहा, द्रह्यस २२ लाख करोड़ रुपये का जीवाश्म ईंधन आयात करते हैं। इससे भी प्रदूषण हो रहा ह्यद्रह्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने २०२३ में २० प्रतिशत एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल पेश किया था। इसमें पहले चरण में १५ शहरों को शामिल किया गया था। गन्ने के साथ-साथ टूटे चावल और अन्य कृषि उत्पादों से निकाले गए एथनॉल के इस्तेमाल से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा। भारत अपनी कच्चा तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए ८५ प्रतिशत आयात पर निर्भर है। ई२० के उपयोग से दोपहिया वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग ५० प्रतिशत और चारपहिया वाहनों में शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लगभग ३० प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। औसतन १० प्रतिशत मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य जून, २०२२ में प्राप्त किया गया, जो नवंबर, २०२२ की समयसीमा से काफी पहले था।